प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ..सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-02, अंक - 51 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 24 सितम्बर 2020 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

यदि आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते है तो करूणा का भाव रखें। यदि आप स्वयं प्रसन्न रहना चाहते है तो भी करूणा का भाव रखें।

दलाई लामा

वोटो के ध्रुवीकरण व असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली बयानबाजी पर लगे रोक

माही की गूंज, झाबुआ। संजय भटेवरा

लोकतंत्र की मूल आत्मा है चुनाव और चुनाव मुद्दों पर आधारित होना चाहिए, भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है यहां चुनाव तो क्या युद्ध तक में विरोधियों का सम्मान किया जाता रहा है। महाभारत के युद्ध में इस बात का प्रमाण है कि, दिनभर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले सैनिक और योद्धा सूर्यास्त के बाद एक दूसरे के शिविरों में जाकर घायलों का उपचार करते थे, उनकी सेवा करते थे, आजाद भारत में शुरुआती चुनाव में भी विरोधियों के सम्मान की परंपरा कायम रही लेकिन पिछले कुछ चुनावों में न केवल भाषा की गरिमा को तार-तार किया है वरन व्यक्तिगत हमले करने से भी नेता बाज नहीं आ रहे हैं। राजनीति में अपनी कमीज को सफेद दिखलाने का सभी को हक है लेकिन दूसरों की कमीज पर कीचड़ उछालना कहां तक जायज है। चुनावों में नेताओं द्वारा सारी मर्यादाए भंग कर दी जाती है गत वर्ष झाबुआ उपचुनाव में भी हमने देखा कि, सत्ताधारी दल ने जिस प्रकार अपनी सत्ता का उपयोग किया, कुछ ऐसा ही नजारा प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में दिखने की पूरी संभावना है और जिसकी शुरुआत नेताओं के अर्नगल बयान-बाजी के साथ प्रारंभ हो चुकी है, दरअसल ये सभी बयान-बाजी असल मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए होती है, जिससे तात्कालिक लाभ के लिए दूसरों की महिमा मंडित किए जाने की परंपरा प्रारंभ हो गई है और असली मुद्दे गौण हो जाते हैं।

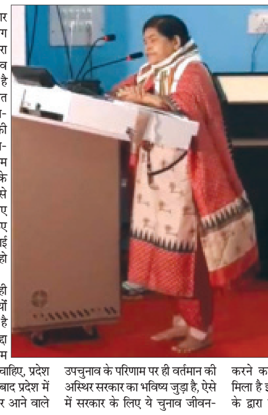

चुनाव के द्वारा ही सरकार के किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक चुनाव का मुद्दा केवल और केवल आम जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, प्रदेश में नाटकीय घटनाक्रम के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ हे और आने वाले उपचुनाव के परिणाम पर ही वर्तमान की अस्थिर सरकार का भविष्य जुड़ा है, ऐसे में सरकार के लिए ये चुनाव जीवन-मरण का प्रश्न है। होना तो यह चाहिए कि, चुनाव में एक दल अपनी बात रखें अपने किए गए कार्यों को बतलाए साथ ही अपनी आगामी योजनाएं आम जनता के सामने रखें, वहीं विपक्षी दल के उम्मीदवार भी अपनी योजनाओं को जनता के सामने रखे और जनता दोनों पक्षों को कसौटी पर रखकर अपना निर्णय दर्ज करें, लेकिन हो रहा है ठीक उल्टा यहां केवल और केवल एक दूसरे की कमियों को ही गिनाया जा रहा है एक दूसरे को महिमा मंडित कर अपने आप को श्रेष्ठ दिखलाने का प्रयास किया जा रहा है।

सवैधानिक दायरे ने रहकर अपने हितों की रक्षा करने का संवैधानिक अधिकार हमें मिला है इसी तारतम्य में अनेक समाज के द्वारा कुछ सामाजिक संगठनों का गठन किया गया है, वे अपने हक और अधिकारों को लेकर अपनी आवाज समय-समय पर उठाते रहते हैं जोकि किसी भी स्थिति में गलत नहीं हो सकता है यदि तरीका संवेधानिक हो, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश की एक महिला मंत्री उषा ठाकुर ने क्षेत्र के एक संगठन के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर दी, जिसके बाद कई स्तरों पर उसका विरोध प्रदर्शन हुआ और बाद में मंत्री को सफाई देना पड़ी, साथ ही अपने कथन के लिए माफी भी मांगना पड़ी, उसके बाद भी मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और विरोध जारी है। जिसको लेकर कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि, ये सब कुछ उपचुनाव के मद्देनजर सोची-समझी साजिश के तहत चल रहा है ताकि वोटो का समाज में फूट डालकर वोटों का धुर्वीकरण किया जा सके और असल मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए और तत्कालीन मुद्दों के आधार पर चुनाव प्रचार केंद्रीय तो हो जाए इन बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि, इस तरह की बयानबाजी पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।

कृषि विधेयकों के खिलाफ केरल सरकार खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली ऐजेन्सी। सीपीआई (एम) की अगुआई वाली केरल सरकार ने तीन दिन पहले संसद में पास किए गए कृषि विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। केरल सरकार ने बुधवार को यह फैसला लेते हुए कहा है कि, मोदी सरकार की ओर से पास कराए गए विधेयक संघीय ढांचे का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि कृषि समवर्ती सूची में आता है।

इससे पहले राज्य के कृषि मंत्री वीसी सुनील कुमार ने कानूनी राय ली थी और उन्हें सलाह दी गई थी कि, इन बिलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और कहा गया कि, केंद्र सरकार का फैसला राज्य की शक्तियों में दखल है और यह संघीय ढांचे के खिलाफ है।

झगड़े से परेशान पत्नी ने की पति की हत्या, शव बेड में छिपाया, खुद ने पुलिस को फोन कर बताई घटना

चुरू, एजेंसी। राजस्थान के चुरू जिले के गांव सांखणताल में एक महिला ने रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर पति की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी और शव बेड में छिपा दिया। करीब 24 घंटे बाद महिला ने खुद ही पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलने पर हमीरवास थानाधिकारी सुभाषचंद्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के घर पर ही शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

सऊदी अरब ने भारत आने-जाने वाली उड़ानों पर लगाई रोक

नई दिल्ली ऐजेन्सी। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर भारत से आने और जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। एक आधिकारिक दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। जारी एक आदेश में सऊदी अरब के नागरिक विमान महाप्राधिकरण (जीएसीए) ने कहा कि, वह निम्नलिखित देशों भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना से आने-जाने वाली यात्रा को निलंबित कर रहा है इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो सऊदी अरब आने से 14 दिन पहले उपरोक्त किसी भी देश में गए हैं।

संसद की मोहरः हिंदी-कश्मीरी-डोगरी को मिला भाषा का दर्जा

नई दिल्ली, एजेंसी। राज्यसभा ने जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 को बुधवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। एक दिन पहले लोकसभा ने इस विधेयक पर मुहर लगाई थी। इस विधेयक के जरिये हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे पहले तक सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी को ही आधिकारिक भाषा का दर्जा था।

टाइम मैगजीन में 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में पीएम मोदी और शाहीन बाग की दादी शामिल

नई दिल्ली ऐजेन्सी। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैग्जीन टाइम ने साल 2020 के सौ सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जगह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा पीएम मोदी उन दो दर्जन नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है।

टाइम मैगजीन की ओर से हर साल यह लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हुए दुनिया को प्रभावित करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। पीएम मोदी इस लिस्ट में इकलौते भारतीय नेता हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को भी जगह दी गई है।

शाहीन बाग में प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में आई 82 साल की बिलकिस, जिन्हें लोग दादी कहकर बुलाते हैं, को भी 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है।

तीसरे दिन भी सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी गिरावट

नई दिल्ली, एजेंसी। बुधवार को लगातार तीसरे दिन भारत में सोने और चांदी की कीमतें कम हुई हैं। एमसीएक्स पर अक्तूबर का सोना वायदा 0.4 फीसदी गिरकर 50,180 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी वायदा 1.6 फीसदी गिरकर 60,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इस सप्ताह दुनिया भर में कीमती धातु की कीमतों में भारी गिरावट आई है। पिछले सत्र में सोने की कीमतों में 100 रुपए की गिरावट आई थी और सोमवार को यह 1,200 रुपए सस्ता हुआ था। मंगलवार को चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई, सोमवार को चांदी की कीमत 6 हजार रुपए कम हुई थी।

प्रधानमंत्री आवास की राशि को लेकर लगातार घिरती जा रही नगर परिषद, एक माह में दूसरी बार धरने पर बैठे हितग्राही

आरोपः सांसद की कार्य क्षमता की कमी के कारण नहीं मिल रहा योजना का लाभ

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद नगर परिषद के अंतर्गत लगभग 2 वर्ष पूर्व स्वीकृत 202 प्रधानमंत्री आवास की राशि आज तक आवंटन नहीं होने से आवास हितग्राहियों में जबरजस्त रोष हैं। आलम यह है कि, पिछले एक माह में दूसरी बार हितग्राही नगर परिषद में पहुंच कर धरने पर बैठ गए। पिछले धरने पर मिले आश्वासन के पूरा नहीं होने पर सोमवार को फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं डलने के बाद हितग्राही एक साथ पेटलावद नगर परिषद पहुंचे। सीएमओ शर्मा के आश्वासन के बाद भी आज तक हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं डाली गई। हितग्राहियों ने बताया कि पूर्व में भी हमारे द्वारा नगर परिषद में राशि को लेकर धरना दिया गया था। जिसके बाद सीएमओ और नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा 15 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन आज दिन तक हमारे खाते में राशि नहीं डाली गई। इसी मुद्दे को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष सीएमओ और हितग्राही के बीच काफी देर तक बहस होती रही। जब हितग्राही नहीं माने तो सीएमओ द्वारा एक लिखित आश्वासन दिया गया। जिसमें लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संबंधित फाइलों को 18 सितम्बर को उपयंत्री सेप्टा के द्वारा एक-एक फाइल को चेक कर पत्र फाइल परियोजना अधिकारी झाबुआ को प्रेषित की जा चुकी है, इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद द्वारा जिला कलेक्टर को अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गई। जिला कलेक्टर के द्वारा अनुमोदन किया जाना शेष है। अब देखना यह होगा कि, हितग्राहियों के खाते में यह राशि कब तक आएगी।

सरकार और उनके नुमाईंदों पर से विश्वास खोती जनता

केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार होने के बाद भी भाजपा की ही योजना का लाभ नहीं मिल पाने के कारणों से नगर की जनता का सरकार और उनके नुमाईंदों से विश्वास उठता ही जा रहा है। आपसी राजनीतिक खिंचतान का हर्जाना परिषद के पार्षदों और आवास हितग्राहियों को भुगतना पड़ रहा है। हितग्राहियों का कहना है कि जो लोग आवास योजना के लिए पूर्ण पात्र है और जिन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। कम से कम उनको तो योजना का लाभ दिया जाए। ताकि पक्के मकान का सपना साकार हो सके।

पार्षद लाला चौधरी का कहना है कि राशि का आवंटन परिषद को होने के बाद दो साल तक हितग्राहियों को भुगतान नहीं होना हास्यास्पद हैं, केवल ये योजना ही नहीं इसकी लेट-लतीफी के कारण अगली खेप में इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

परिषद में विधायक प्रतिनिधि जीवन ठाकुर ने भाजपा पर आरोप जड़ते हुए कहा कि भाजपा आपसी फूट और भाजपा के सांसद गुमानसिंह डामोर की कार्य क्षमता की कमी के कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजनीति से उठकर जनता के भले के लिए लिए कार्य करने का समय है जो कि नहीं किया जा रहा है।

क्या यही है शिवराज सरकार का सुशासन ?

माही की गूंज, झाबुआ। मुज्जमील मंसुरी

प्रदेश की शिवराज सरकार भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिवस को सुशासन सप्ताह के रूप में प्रदेश भर में सेवा कार्यों से मनाया जाता है, लेकिन एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी शासकीय सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके वारिस को साल भर बाद भी यह पता नहीं चल पाता है कि उनके परिजनों को सेवानिवृत्ति पर किस-किस मद में कितनी राशि मिली। सूचना अधिकार के तहत कई बार आवेदन देने के बाद भी लगभग सात-आठ माह बाद विभाग द्वारा गोलमाल जवाब देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। क्या शिवराज सरकार का यही सुशासन है?

हम बात कर रहे हैं बामनिया निवासी स्व. बाबूलाल खोड़े व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलाबाई खोड़े की। जो 1992-93 से लगाकर सेवानिवृत्ति तक नगर पंचायत थांदला में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे, सेवानिवृत्ति के बाद उनके पोत्र तथा सूचना अधिकार कार्यकर्ता किशन खोड़े ने 7 जनवरी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत 4 बिंदु की जानकारी नगर पंचायत थांदला से मांगी। जिसमें उन्होंने अपने दादाजी तथा दादी की जीपीएफ-डीपीएफ की पासबुक की सत्यापित छायाप्रति, उक्त दोनों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर किए गए भुगतान की राशि व भुगतान के प्रकार की जानकारी, जिसमें नगदी या बैंक से किए जाने पर पत्रक की छायाप्रति, परिवार कल्याण निधि की जानकारी तथा बीमा की राशि का ब्यौरा, अवकाश नगदी कर की जानकारी मय प्रमाणित प्रति के साथ मांगी गई। लेकिन नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद 29 फरवरी को श्रीमान संयुक्त संचालक महोदय इंदौर के नाम पत्र लिखकर सूचना अधिकार के अंतर्गत जानकारी दिलाने की मांग की गई, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुनः एक पत्र 11 मई को श्रीमान संयुक्त संचालक महोदय नगरीय प्रशासन तथा विकास अधिकारी संभाग इंदौर को लिखा गया। जिसमें सूचना अधिकार के मखोल उड़ाए जाने का हवाला दिया गया। इसके साथ ही 14 जुलाई को एक पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला को भेजा गया। जिसमें पूर्व के पत्रों का हवाला देकर तथा नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक चौहान के साथ चर्चा का हवाला देकर उक्त जानकारी दिलवाने की मांग की गई। किशन का कहना है कि इस दौरान मुझे कई बार नगर पंचायत द्वारा झूठा आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं दी गई। उसके कई दिनों बाद मुझे 29 अगस्त को नगर पंचायत द्वारा गोलमाल जानकारी दी गई। जिसमें मेरे किसी भी बिंदु की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

दी गई जानकारी में किया गुमराह

बिंदु क्र.1- जीपीएफ अधिकारी तथा कर्मचारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान होता था वर्तमान में इनकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बिंदु क्र.2 - परिवार कल्याण निधि तथा पेंशन की राशि सीधे भोपाल से संबंधित के खाते में जमा होती है।

बिंदु क्र.3 - बीमा कंपनी प्राइवेट कंपनी है निकाई से कोई संबंध नहीं है।

बिंदु क्र.4 - संबंधीतो कि सर्विस बुक भोपाल में होने से छुट्टियों का लेख भोपाल में है।

इस प्रकार के उत्तर देकर नगर पंचायत ने तो सुचना अधिकार का मखोल उड़ाकर गुमराह करते हुए अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का प्रयास किया है, लेकिन क्या यह सही है? कोई भी कर्मचारी अपनी पूरी सेवाएं निकाय में देता है, उसे कितना मिल रहा है, कितना कट रहा है तथा मृत्यु पर कितनी राशि मिलेगी। यह जानने का उसे व उसके परिवार को हक है। उनकी मेहनत की कमाई का हिस्सा तो निकाई द्वारा काटा जाता है, लेकिन हिसाब निकाय के पास नहीं है? बीमा की राशि मानदेय से काटी जाती है, लेकिन हिसाब कंपनी के माथे पर डाल दिया जाता है? निकाय के पास कोई हिसाब नहीं है, सीधे भोपाल पर जिम्मेदारी डालकर निकाय ने अपनी जिम्मेदारी भोपाल पर डाल दी है। एक रिटायर्ड कर्मचारी या उसके परिवार को यह जानने का हक भी नहीं है कि, उन्हे सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कितनी राशि का भुगतान किया गया है। क्या शिवराज सरकार का यही सुशासन है? इस प्रकरण के बाद तो यही कहा जा सकता है कि सब गोलमाल है भई सब गोलमाल।

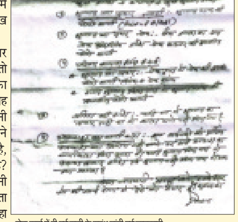

सेवा कार्य में दी गई राशी के सबंध मांगी गई जानकारी

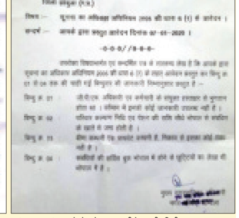

थांदला नगर पंचायत ने गोलमोल जानकारी देकर की इतिश्री

नाक के जरिए दी जाएगी वैक्सीन, भारत बायोटेक ने किया अमेरिकी यूनिवर्सिटी से समझौता

नई दिल्ली ऐजेन्सी। कोरोना वायरस के लिए भारत बायोटेक कंपनी नाक के जरिए ली जाने वाली एक विशेष वैक्सीन विकसित कर रही है। भारत बायोटेक ने इसके लिए अमेरिका के सेंट लुईस में स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफमेडिसिन के साथ एक समझौता किया है। इस वैक्सीन को कोरोफ्लू नाम दिया गया है।

भारत बायोटेक ने कहा है कि, कंपनी के पास अमेरिका, जापान और यूरोप को छोड़कर अन्य सभी बाजारों में वैक्सीन के वितरण का अधिकार होगा। कंपनी ने बताया कि इस वैक्सीन के पहले चरण का परीक्षण सेंट लुइस विश्वविद्यालय की इकाई में होगा, जबकि नियामक मंजूरियां हासिल करने के बाद भारत बायोटेक अन्य चरणों का परीक्षण भारत में भी करेगी।

पूर्व में हुए एक अध्ययन में ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि कोरोना के लिए वैक्सीन इन्हेलर के रूप में या नाक के स्प्रे के रूप में ज्यादा प्रभावी साबित होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों का मानना है कि सीधे फेफड़े में दवा डालना बेहतर तरीका हो सकता है।

सदमे में सरकार, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री का कोरोना से निधन

नई दिल्ली, एजेंसी। देश मे कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बड़ी खबर मिल रही है की केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन हो गया हैं। मिली जानकारी के अनुसार अंगड़ी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के निधन से सरकार सदमे में है। सामान्य वायरस से शुरू हुआ कोरोना अब वीआईपी तक पहुँच गया है, अलग-अलग राज्यो में मंत्री, पूर्व मंत्री और बड़े नेता जान गवा चुके हैं , बीते 11 सितंबर को रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने ट्वीट करके खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के वे पहले मंत्री हैं, जिनकी जान कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हो गई है, वह करीब 65 वर्ष के थे।

हाईकोर्ट के निर्देश का दिखेगा असर, भोपाल में रहेगा सिंधिया का डेरा

तीसरे राउंड में दस सीटों पर पहुंचेगी शिवराज-सिंधिया की जोड़ी

चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के पहले ही ग्वालियर-चंबल अंचल के दो दौरे कर चुकी प्रदेश की सियासत की नई जोड़ी एक बार फिर विधानसभा क्षेत्रों में उतरने को तैयार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले दो दौरों में छोटी विधानसभा सीटों पर पहली बार एक-साथ दस्तक देने जा रही है। इस जोड़ी का यह तीसरा राउंड 24 सितंबर से शुरू होगा। इस राउंड में यह जोड़ी उपचुनाव वाले दस विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। दिग्गजों की इस जोड़ी के दौरे पर हाईकोर्ट के आदेश का असर भी दिखाई दे सकता है।

भोपाल

मुख्यमंत्री चौहान और सांसद सिंधिया इस बार भोपाल में रहकर ही अपना तीन दिनी दौरा पूरा करेंगे। इसके लिए सिंधिया 24 सितंबर को भोपाल पहुंच रहे हैं। दोनों नेता हर रोज तीन विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। पहले दिन मुंगावली, अशोक नगर और डबरा में कार्यक्रम रखे गए हैं। अगले दिन बमोरी, सुरखी और सांची का दौरा रहेगा तो अंतिम दिन दोनों दिग्गज बदनावर, सांवेर और हाटपिपल्या पहुंचेंगे। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सभाओं के अलावा स्थानीय कार्यक्रम रखे गए हैं। दौरे के अंतिम दिन बदनावर के ग्राम कोद में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। साथ ही कोटेश्वर मंदिर में दर्शन भी करने जाएंगे। मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में दोनों दिग्गजों का यह पहला दौरा है। इसके पहले यह जोड़ी चंबल-ग्वालियर क्षेत्र में दो बार एकसाथ दौरे कर चुकी है। तीन दिनी सदस्यता अभियान के बाद अंचल की एक दर्जन सीटों पर इस जोड़ी ने अपनी धमक दिखाई थी। संसद शुरू हो जाने के कारण सिंधिया दिल्ली चले गए थे। इसके बाद मालवा और निमाड़ की सीटों पर मुख्यमंत्री चौहान अकेले ही पहुंचे हैं।

अब हाईकोर्ट का भी शिकंजा

कोरोना काल में राजनीतिक कार्यक्रमों में एकत्रित हो रही भीड़ के कारण संक्रमण फैलने का अंदेशा जताते हुए एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने गतदिवस ही गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने कहा है। इसमें कलेक्टरों को हिदायत दी गई है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाए। इस आदेश का असर सीएम चौहान और सांसद सिंधिया के दौरे व कार्यक्रमों पर भी दिखाई दे सकता है। जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस को भी सक्रियता दिखाना पड़ेगी। स्थानीय नेताओं को भी प्रशासनिक अनुमति के साथ सोशल डिस्टेंसिंग व भीड़ पर नियंत्रण के लिए कदम उठाना होंगे।

भोपाल में ही रुकेंगे सिंधिया

इस तीन दिनी दौरे के लिए सांसद सिंधिया भोपाल में ही रहेंगे। पहले दो दिन रात्रि विश्राम भी वे भोपाल में ही करेंगे। दौरे पर निकलने के पहले और देर रात तक सिंधिया भोपाल में रहकर भेंट-मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र का पिछले दौरे में भी सिंधिया को भोपाल में ही रुकना था, लेकिन अंतिम समय पर कार्यक्रम बदल गया था और वे ग्वालियर में ही रुके थे।

ग्वालियर-चंबल की नौ सीटों पर गुर्जरों का दबदबा

गुर्जरों को साधने कमल नाथ का प्रोजेक्ट 'पायलट'

भोपाल

मप्र के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का सारा फोकस ग्वालियर-चंबल संभाग पर है। यही वजह है कि कमल नाथ सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है, वहीं अब वो गुर्जर बाहुल्य सीटों पर मतदाताओं को रिझाने के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाने जा रही है। मप्र की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से 16 सीटें ऐसी हैं, जो सिंधिया के गढ़ यानी ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की हैं। इन 16 सीटों में से 9 सीटें तो गुर्जर बाहुल हैं तो कांग्रेस सिंधिया को चुनौती देने के लिए सचिन पायलट को उतारने की तैयारी कर रही है।

मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इन सीटों में से अधिकांश सीटें सचिन पायलट के साथ पूर्व में कांग्रेस के लिए लंबे समय तक काम कर चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर-चंबल में हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने 20 सितंबर को राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से खासकर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने का अनुरोध किया और पायलट ने इसके लिए तुरंत अपनी सहमति भी दे दी है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान पड़ोसी राज्य हैं। इसलिए पायलट मध्य प्रदेश के साथ-साथ यहां की राजनीति से भी अच्छी तरह से परिचित हैं। पायलट ने नवंबर 2015 में रतलाम-झाबुआ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के लिए चुनाव प्रचार किया था और तब भूरिया ने इस सीट पर जीत हासिल की थी।

पायलट के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस को गुर्जर समुदाय के मतदाताओं को अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए लुभाने में मदद मिल सकती है। पायलट ने जुलाई में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी और सिंधिया की तर्ज पर उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा होने लगी थी। बाद में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद पायलट अपनी पार्टी कांग्रेस में वापस लौट आए। मार्च में कांग्रेस के 22 विधायकों ने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ-साथ कांग्रेस छोड़ी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से अधिकांश विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की कमल नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा फिर से सत्ता में आई है। मप्र की कुल 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटें रिक्त हैं, जिन पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने से खाली हुई हैं, जबकि दो सीटें कांग्रेस के विधायकों के निधन से और एक सीट भाजपा विधायक के निधन से रिक्त है। हालांकि चुनाव आयोग ने फिलहाल उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है।

सिंधिया के दोस्त हैं सचिन पायलट

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मित्र हैं। जब राजस्थान में सचिन पायलट ने पार्टी से बगावत की थी, तब सिंधिया ने पायलट के समर्थन में कई ट्वीट किए थे। ऐसे में कांग्रेस उनके सामने सचिन पायलट को उतारकर गुर्जर बाहुल्य सीट पर फायदा उठाना चाहती है।

बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में मारपीट

बुरहानपुर। नेपानगर विधानसभा सीट से विधायक सुमित्रादेवी कास्डेकर के विधायकी से इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर भाजपा पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क और सभाएं कर रही है, जिसके चलते बीते शनिवार को भाजपा ने ग्राम डेढ़तलाई में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद नंदकुमारसिंह चौहान और भाजपा प्रत्याशी सुमित्रादेवी कास्डेकर पहुंचे, जहां उन्हें ग्रामवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों के विरोध का मुख्य मुद्दा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टंट्या महाराज की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर था, इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध करते हुए बताया कि, गांव में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टंट्या महाराज की प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक यहां पर प्रतिमा नहीं लगाई गई है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने भाजपा सांसद के सामने ही जमकर हंगामा किया, इसी बीच कुछ लोगों के बीच लात घूंसे चले और जमकर मारपीट भी हुई।

ग्रामीण तय करते हैं 2 किमी का सफर

कांग्रेस विधायक के गृह क्षेत्र में नहीं पीने का पानी

सिवनी

लखनादौन विधानसभा से कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह की छवि काफी स्वच्छ है, भले ही वे मिलनसार हैं लेकिन अपने ही गांव के लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कभी-कभी ग्राम वासियों से दो चार होना पड़ता है। सिवनी जिला भारी बारिश के चलते बाढ़ और अतिवृष्टि से परेशान रहा है, वहीं दूसरी ओर लखनादौन विधानसभा की ग्राम पंचायत और कांग्रेस विधायक के गृह ग्राम धूमा में लोग पेयजल नहीं मिलने से परेशान हैं। न यहां नलजल योजना संचालित है और न ही कोई टैंकर की व्यवस्था है। जानकारी के मुताबिक मजबूरी में गांव से दो किमी दूर लगे हैंडपंप से पानी ढोने को मजबूर हैं और ऐसे में बच्चे-बूढ़े सभी सुबह से शाम तक पीने के पानी की जद्दोजहद में लग जाते हैं। विधायक को अपने गांव के ग्रामीणों की चिंता ही नहीं है, अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भारी बरसात में पीने के पानी के लिए गांव से दो किमी दूर जाना पड़ता है तो गर्मी और ठंडी के दिनों में ग्रामीण कितने परेशान हो जाते होंगे। योगेंद्र सिंह ने अपने गृह ग्राम में विकास कार्य के नाम पर 2017 में 12 लाख की लागत से बच्चों के खेलने के लिए गार्डन का निर्माण कराया गया है। लेकिन उसमें भी न तो झूलों का पता है और न ही कुर्सियों का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विधायक को अपने ही गांव की चिंता क्यों नहीं है। बहरहाल, अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद विधायक को अपने ग्रामवासियों का मर्म दिखाई देगा या नहीं ग्रामीणों की परेशानी जारी रहेगी।

छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के पूर्व मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के 77लाख किसानों को प्रति वर्ष तीन किश्तों में दो 2-2 हजार रुपये, कुल रुपए 6000 प्रति किसान प्रदान किए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष दो किस्तों में दो दो हजार रुपये कुल रुपए 4000 की सम्मान देने का फैसला किया है। केंद्र व राज्य सरकार की इन योजनाओं की कुल राशि अब रुपए 10000 हो जाएगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के सभी किसानों को लाभ होगा। विशेषकर छोटे किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी।

सभी किसानों को देंगे लाभ -मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों का सर्वे कर प्रदेश के प्रत्येक किसान को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देगी। प्रदेश में खातेदार किसानों की अनुमानित संख्या एक करोड़ है।

25 सितंबर को प्रारंभ होगा राशि वितरण- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत के किसानों को सम्मान निधि की पहली किस्त के वितरण की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर दी जाएगी। उस दिन किसानों के खातों में मुख्यमंत्री स्वयं भोपाल से तथा मंत्री गण व अन्य जनप्रतिनिधि अन्य जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में राशि अंतरित करेंगे।

बगावत के भंवर को आस्था की टक्कर

बदनावर में आसान नहीं बगावत को दबाना दत्तीगांव को चलना होगा नया दांव

भोपाल

मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। धार जिले की बदनावर इस वक्त सबसे चर्चित सीट है। पिछले चुनाव में यहां मुकाबला भाजपा के भंवरसिंह शेखावत और कांग्रेस के राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के बीच हुआ। इस मुकाबले में भाजपा से बगावत करके राजेश अग्रवाल मैदान में उतरे। अग्रवाल ने 35000 से ज्यादा वोट हासिल किया। उनके मैदान में उतरते ही भाजपा की हार तय सी दिख रही थी। अब खुद राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भाजपा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले चुनाव के बागी राजेश अग्रवाल को फिर से भाजपा में शामिल कर लिया। इससे तमतमाए भंवरसिंह शेखावत ने कैलाश और पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेश अग्रवाल को उनके खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय ने ही खड़ा किया था। बदनावर से चुनाव लड़ने वाले राज्यवर्धन सिंह अब शिवराज सरकार के मंत्री भी है। भाजपा का साथ है, ऐसे में अभी उनका पलड़ा भारी दिख रहा है।1957 में यहां पहली बार उपचुनाव हुआ था इसके बाद कभी भी उपचुनाव नहीं हुआ। राजपूतों के बाहुल्य वाले इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन दशक से जातिवाद हावी रहा है। जातिगत समीकरणों को चलते ही दोनों दल प्रत्याशियों को टिकट देते रहे हैं। बदनावर में राजपूत समाज के 28000 से अधिक मतदाता हैं। यहां से केवल एक बार पाटीदार समाज के भाजपा प्रत्याशी खेमराज पाटीदार जीते हैं। समाज के करीब 24 हजार मतदाता हैं। 6 बार राजपूत, 3 बार ब्राह्मण, 2 बार वैश्य, 1 बार कायस्थ समाज के प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। यहां सवर्ण हमेशा ही पाला बदलते रहे हैं। हालांकि इस बार हालात इतने बदले हुए हैं कि कांग्रेस से दल बदलकर गए नेता ही अब भाजपा का झंडा उठाएंगे।

बदनावर विधानसभा

- 97877 पुरुष
- 96810 महिलाएं
- कुल 194687 मतदाता

कब कौन रहा विधायक

- 1957 मनोहरसिंह मेहता कांग्रेस
- 1962 गोवर्धन जेएस
- 1967 गोवर्धन बीजेएस
- 1972 सिरोजीलाल अत्राया कांग्रेस
- 1977 गोवर्धन शर्मा जेएनपी
- 1980 रघुनाथ सिंह कांग्रेस
- 1985 रमेश चंद सिंह बीजेपी
- 1990 प्रेम सिंह दौलत सिंह कांग्रेस
- 1993 रमेश चंद सिंह राठौर पुत्र बीजेपी
- 1998 खेमराज पाटीदार बीजेपी
- 2003 राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस
- 2008 राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस
- 2013 भंवर सिंह शेखावत बीजेपी
- 2018 राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस

1998 से बदनावर के पूरक रहे हैं दत्तीगांव

दत्तीगांव ने बदनावर विधानसभा से पांच बार चुनाव लड़ा है। इसमें पहली बार 1998 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय के रूप में लड़े और पहले ही प्रयास में दत्तीगांव ने करीब 30 हजार वोट हासिल किए। हालांकि इसके बाद हुए 2003 के चुनाव में कांग्रेस ने दत्तीगांव को टिकट दिया। इसमें भी विजयी हुए। इसके बाद लगातार दूसरी बार 2008 में भी विधायक चुने गए। 2013 में उन्हें भाजपा के भंवरसिंह शेखावत ने पराजित किया। 2018 में दत्तीगांव ने अपनी हार का बदला लेते हुए शेखावत को ही 41 हजार मतों के अंतर से हराया।

जातिगत समीकरण यहां का खास

यहां पर मुख्य रूप से वोटों की राजनीति के मामले में जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में दोनों ही बड़ी पार्टी के उम्मीदवार राजपूत समाज से हैं। राजपूत और पाटीदार समाज का बाहुल्य है। ऐसे में जो वर्ग जिस नेता के साथ चल पड़ता है उसके लिए राह आसान होती है। लेकिन इसमें संतुलन बनाना भी पार्टियों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस लिहाज से यहां पर जिसने दोनों वर्गों को साध लिया वह नतीजे के लिए आश्वस्त हो जाता है। पिछले 20 सालों से यहां राजपूत वोटबैंक का दबदबा रहा है। उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद रणनीति बना रहे है साथ ही एक एक सीट पर दावेदार और असंतुष्ट नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि दत्तीगांव के सामने कांग्रेस से कौन हुंकार भरेगा।

राज्यवर्धन की राह दिख रही आसान

धार जिले की बदनावर सीट पर औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने 2018 में भाजपा के भंवर सिंह शेखावत को 41,506 वोट से हराया था। जबकि वोटकटवा उम्मीदवारों को 9,177 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में यहां 8 प्रत्याशी मैदान में थे और कुल 1,67,645 वोट पड़े थे। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को 84,499, शेखावत को 42,993 और निर्दलीय राजेश अग्रवाल को 30,976 वोट मिले थे। राजवर्धन का जन्म 20 जनवरी 1972 को जयपुर में हुआ था। दत्तीगांव को महाराजा या राव साहेब के नाम से भी जाना जाता है। पेशे से यह किसान और व्यवसायी हैं। इन्होंने आईआईएमसी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। भाजपा को विश्वास है की उप चुनाव में दत्तीगांव इस सीट पर जरूर जीत हासिल करेंगे। लेकिन पार्टी में जिस तरह का उनका विरोध दिख रहा है उससे मिसाइल का खतरा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि राजवर्धनसिंह दत्तीगांव ज्योतिरादित्य के कट्टर समर्थक हैं और उनका एक इशारा होते ही पार्टी और पद दोनों ही त्याग दिए। उनकी इस स्वामी भक्ति ने बदनावर को उपचुनाव के रूप में धकेल दिया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दत्तीगांव अब दलबदलू बनकर भाजपा के टिकट पर चुनाव में उतरेंगे तो क्या उनके पुराने कांग्रेसी साथी और कांग्रेसी मतदाता उन्हें भाजपा की ओर से चुनेंगे।

कांग्रेस के स्थानीय दावेदारों ने भरी हुंकार!

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का बदनावर से उपचुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस में टिकट को लेकर जहां मंथन चल रहा है तो वहीं कई दावेदार टिकट की आस लिए बदनावर से कांग्रेस दफ्तर तक दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस में स्थानीय दावेदार की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। बदनावर से करीब 16 स्थानीय उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता रहे हैं, जिनके साथ पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक कर चुके हैं। स्थानीय नेताओं में कमल सिंह पटेल, ईश्वर सिंह पन्नालोढ़ी, अभिषेक मोदी, सुनील सांखला, भंवर सिंह सिसोदिया, दिलीप पाटीदार आदि नेताओं द्वारा अपना नाम प्रमुखता से रखा गया है। हालांकि कमलनाथ स्पष्ट कर चुके है कि सर्वे में जो सबसे आगे होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। उधर सूत्रों का कहना है कि राजपूत वोटों का गणित परिणामों को प्रभावित करते रहे हैं इस कारण से कांग्रेस इस बार वरिष्ठ नेता अजय सिंह पर दांव लगा सकती है। हालांकि कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि जाति को ही आधार बनाकर सीट जीतने की रणनीति कांग्रेस भी बनाएगी। हालांकि भंवर सिंह शेखावत भी भाजपा में आए बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने को लेकर विरोध जता चुके हैं। वे यहां तक धमकी दे चुके हैं कि यदि दलबदलू को टिकट दिया गया तो वे सामने से चुनाव में उतरेंगे।

राम के नाम पर वोट मांगने का मामला

कांग्रेस ने खटखटाया चुनाव आयोग दरवाजा

सागर। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। सुरखी से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में उनके कार्यकर्ता भगवान राम के नाम पर वोट मांगते नजर आए थे। जिसके बाद कांग्रेस ने मामले में निर्वाचन आयोग से कार्रवाई करने की अपील की है। वहीं बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो चुकी सुरखी से पूर्व विधायक और कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी पारुल साहू ने इसे धर्म से जुड़ा मामला बताया। उन्होंने कहा कि इंसान, इंसान को धोखा दे सकता है लेकिन भगवान को नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, सुरखी में इस बात का फैसला अब जनता ही करेगी। वहीं मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कहा है कि भगवान राम बीजेपी पार्टी के लिए कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। भगवान राम हो या कृष्ण यह आस्था का विषय है।

पशुपालकों को मिला योजना का लाभ

माही की गूंज, मेघनगर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. शाखा मेघनगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर नए केसीसी ऋण का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में तोलाराम मुनिया सहकारिता विस्तार अधिकारी मेघनगर, पशु चिकित्सक गौड़, शाखा प्रबंधक मन्नू सिंह खतेडिया ने कार्यक्रम को संबोधित किया व योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक कृषको बताई। 10 कृषकों को केसीसी पशुपालन क्रेडिट कार्ड वितरण किए गए। प्रमाण-पत्र प्राप्त कर पशुपालकों नें शासन की इस योजना का धन्यवाद अर्पित किया, कार्यक्रम का संचालन शाखा पर्यवेक्षक संजय नागर ने किया।

अजनार को यूथ विंग का कांग्रेस जिलाध्यक्ष किया नियुक्त

माही की गूंज, अलिराजपुर। राहुल गांधी विचार मंच की प्रदेश कमेटी ने जितु अजनार को अलिराजपुर जिले का युथ विंग का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया उक्त नियुक्ती पर जोबट, अलिराजपुर के विधायक के साथ सभी कांग्रेस पदाधीकारियों ने बधाई दी है।

सोलंकी मप्र कर्मचारी कांग्रेस के जिला संगठक तथा संरक्षक मनोनीत

माही की गूंज, झाबुआ। मप्र कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश संरक्षक विरेन्द्र खंगेला की अनुसंशा पर संगठन के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष सुनिल ठाकरे ने संगठन के झाबुआ जिलाध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त भेरूसिंह सोलंकी को उनकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नित करते हुए मप्र कर्मचारी कांग्रेस का जिला संगठक तथा जिला संरक्षक झाबुआ के पद पर पदोन्नत किया है। सोलंकी को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें जिला, समस्त तहसील तथा विकासखंड स्तर के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर संगठन को मजबूत तथा सुदृढ़ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भौतिक सत्यापन के नाम पर विभाग में चल रहा है वसूली का गौरख धंधा

प्राचार्य हुक्कू को आखिर क्यों हुआ कारण बताओ नोटिस जारी

वर्षो से जमे हुए प्राचार्यों के खिलाफ आवाज कब होगी बुलंद

माही की गूंज, पेटलावद।

आदिवासी विकास विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और वसुली के गोरख धंधे में एक ओर भाग सामने आया है। पेटलावद विकास खण्ड के लगभग 16 संकुलो में वर्षो से जमे हुए प्राचार्य जिनके एक संस्था सहित संस्था के दायरे में आने वाली 25 से 30 स्कूल आती है जिसकी जिम्मेदारी संकुल प्राचार्य के पास होती है, जिले के पेटलावद विकास खंड में संकुल क्षेत्र में कई प्राचार्य अपने प्रभाव, अधिकारियों की मिलीभगत और सत्ता में बैठे अपने आकाओं के दम पर वर्षो से एक ही संस्था में जमे बैठे हैं, सैकड़ो शिकायतो का अंबार विभाग और कलेक्टर कार्यालय की धूल खा रहे है लेकिन हर बार ये अंगद की तरह अपने पैर जमाए बैठे की तरह इनको कोई अधिकारी अपनी जगह से नही हिला सका है, शासकीय रिकॉड देखा जाए तो ऐसे कई प्राचार्य हैं जिनको केवल पेटलावद विकास खंड में वर्षों हो चुके हैं।

प्राचार्य संजय हुक्कू इस चैनल की मामूली और कमजोर कड़ी

करवड़ प्राचार्य संजय हुक्कू भी लगातार पेटलावद विकास खण्ड में जमे हुए हैं, खुद पेटलावद के खण्ड शिक्षा अधिकारी भी रह चुके है। सूत्रों के मुताबिक हुक्कू इस विभाग में सबसे कमजोर कड़ी है फिर भी अपने प्रभाव के दम पर विकास खंड में टिके हुए है, जबकि इनके ही संधी साथी इनसे कई गुना प्रभावशाली है इसलिए जिले के अधिकारियों की गिरने वाली गाज ओर कार्यवाही हुक्कू और इनके जैसे प्राचार्य तक सीमित रहती हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी झाबुआ द्वारा दिनाक 7 सितम्बर को कारण बताओ सूचना पत्र अध्यक्ष एस.एम.डी.सी. एवं संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. संजय हुक्कू करवड़ को जारी किया गया जिसमे प्राचार्य हुक्कू पर गम्भीर आरोप लगे हैं।

1- संकुल अंतर्गत हाई स्कूल उ.मा.वि. में रा.मा.शि.अ. अंतर्गत क्रय उपलब्ध सामग्री का भौतिक सत्यापन हेतु समिति का गठन करने एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है, लेकिन प्रभारी प्राचार्य/शिक्षको के द्वारा शिकायत की गई है कि, आपके द्वारा भौतिक सत्यापन के नाम पर राशि की मांग की है एवं राशि प्राप्त भी की है, जबकी भौतिक सत्यापन के लिए प्राचार्य हुक्कू को केवल समिति गठित करनी थी।

2 - एस.एम.डी.सी. शा.उ.मा.वि. करवड़ के अंतर्गत गत 3 वित्तिय वर्ष में प्राचार्य हुक्कू द्वारा नियमानुसार राशि का व्यय नहीं किया गया है तथा निर्धारित तीनो समितियों की बैठके समय-समय पर नही की जा रही है, जिससे छात्र हित प्रभावित हुआ है।

3- कोविड-19 के दृष्टिगत व्हाटसअप ग्रुप के माध्यम से सामग्री भेजी जा रही है, किन्तु प्राचार्य हुक्कू ने अपने मोबाईल में इस तरह का विकल्प डाल रखा है जिससे प्राचार्य को जिला स्तरीय प्राचार्य एवं अन्य ग्रुप में नहीं जोड़ा जा सकता है। इससे स्पष्ट है की प्राचार्य हुक्कू लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक 2063 भोपाल 13 जुलाई तथा कार्या आयुक्त आदिवासी विकास के पत्र कमांक/1031 3 जुलाई का उल्लंघन कर रहे है जो छात्रहित के विपरीत होकर पदीय दायित्यों का निर्वहन नही करना तथा कदाचरण की श्रेणी में आता है।

प्राचार्य संजय हुक्कू पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर और चोकाने है, लेकिन भ्रष्टाचार के समंदर के प्राचार्य संजय हक्कु मामूली मछली है और इससे भी बड़े-बड़े मगरमच्छ इस समंदर मे मौजूद हैं जो हर काम के बदले राशि की माँग करते हैं और शिक्षक मुह माँगी राशि उन्हें देते हैं और चूँ तक नहीं बोलते, क्योकि वो वर्षो से जमे हुए हैं साथ ही स्थानीय भी है जिस कारण उन्होंने अपनी धाक जमा रखी हैं, इन संकुल प्राचार्यो के प्रभाव के खिलाफकोई बोलता नहीं है और कोई बोल जाता है तो उल्टा उसे ही विभाग की भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होना पड़ता हैं।

दोषी पाए जाने पर एसएमडीसी अध्यक्ष पद से विरत होंगे हुक्कू

प्राचार्य हुक्कू को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि, लापरवाहीयों / अक्षमाताओं/कदाचरण पाई जाती है प्राचार्य हुक्कू को एस.एम.डी.सी. अध्यक्ष के दायत्वि से मुक्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारीयो की अनुशंसा की जा सकती हैं ? कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर प्रमाण सहित दिनाक 23 सितम्बर को अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश थे, यदि प्राचार्य हुक्कू समय पर अपनी और से जबाब नही देते तो विभाग उनके विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा बिना हुक्कू का पक्ष जाने कर देगा लेकिन यहाँ संशय की स्थिति उतपन्न हो रही हैं, क्योंकि ये पहला अवसर नही है जब किसी प्राचार्य को या संस्था प्रमुख को भारी लापरवाही, भ्रष्टाचार और अधिनस्तो से पैसो की मांग की शिकायत नही हुई हो, लेकिन जिले के इतिहास में खासकर पेटलावद विकास खण्ड में ऐसा कोई ट्रेक रिकॉर्ड नही है जिसका उदाहरण दिया जा सकता है। प्राचार्य संजय हुक्कू पूर्व में भी चुनावी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित हो चुके हैं, इतना ही नही बीईओ के कार्यकाल में गम्भीर आरोपो सहित करवड़ प्राचार्य के पद पर भी संस्था में रोज नही आने, अपडाउन कर संस्था में लेट आने, अधिनस्त शिक्षकों का वेतन बिना कारण रोकने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही हुई, इस बार भी संभवतः यही परिणाम होंगे, जिससे दूसरे पुराने जमे प्राचार्यो पर हुक्कू पर होने वाली कार्यवाही उदहारण नही बन सके।

लापरवाही बरतने वाले 11 शिक्षकों को भी कारण बताओ नोटिस

करवड़ प्राचार्य संजय हुक्कू के बाद करवड़ स्कूल के शिक्षकों को ''हमारा घर हमारा विद्यालय'' ऑनलाइन बच्चों को अध्यापन कराने के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में स्कूल के शिक्षकों द्वारा कोई रुचि ना लेना तथा बच्चों को कराए गए अध्यापन की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को ना देने का खामियाजा शिक्षकों को अब भारी पड़ रहा है, वरिष्ठ कार्यालय द्वारा इनकी गलतियों को गंभीर लापरवाही मानकर संबंधित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सहायक अध्यापक दशरथ मैडा, उच्च श्रेणी शिक्षक भंवरसिंह सिसोदिया, वरिष्ठ अध्यापक जयंत कुमार श्रीवास्तव, सहायक शिक्षक जितेंद्र सिंह पवार, उच्च श्रेणी शिक्षक कैलाशचंद्र खेर, वरिष्ठ अध्यापक नंदकिशोर पाटीदार, अध्यापक पारगी डामोर, वरिष्ठ अध्यापक प्रेमसिंह मैडा, वरिष्ठ अध्यापक रमेशचंद्र चौहान, अध्यापक सुनीता भीदा एवं सहायक अध्यापक संभव कुमार गामड शामिल है।

आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी प्राचार्य संजय हुक्कू और शिक्षकों को जारी कारण बताओ नोटिस।

क्रेडिट कार्ड-ऋण के प्रमाण पत्र वितरित

- सबको साख सबका विकास के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन

माही की गूंज, झाबुआ। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत सहकारिता विभाग द्वारा यहां नवीन जिला पंचायत सभा कक्ष में सबका साख सबका विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर रोहित सिंह ने इस कार्यक्रम का मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्जलीत कर शुभारम्भ किया। कलेक्टर सिंह ने इस कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी सुखी, स्वस्थ और निरोग्य हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सबका तथा पूरे समाज का विकास होना चाहिए। प्रदेश के साथ-साथ झाबुआ जिले में भी गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसका उद्देश्य यह है कि जिले में कही भी कोई गरीब न हो और कोई धन सम्पदा का अभाव है तो शासन आगे बढ़कर उसका सहयोग करें। शासन की मंशा के अनुरूप जिले में हम यह प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा केसीसी प्रदान करें।

सिंह ने कहा कि पशुपालकों, मत्स्य पालकों को केसीसी के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में 6 हजार केसीसी बनाए जाने का लक्ष्य है। हम जल्दी ही लक्ष्य पूर्ति कर लेगें। जिले में अब तक 3 हजार 544 आवेदन बैंकों को प्राप्त हो चुके हैं। जिनमें से अब तक 741 हितग्राहियों के केसीसी बनाए जा चुके हैं। मत्स्य पालन के हितग्राहियों के लिए 108 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके विरूद्ध 27 हितग्राहियों को केसीसी दिए जा चुके हैं। किसान समान निधि योजना के तहत जिले में 2 हजार 543 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। पशुपालन के लिए 406 हितग्राहियों को एक करोड़ एक लाख रूपए की राशि वितरित की जा चुकी है। बैंक द्वारा किसानों को फ्लस ऋण खरीब 2020 के लिए 55 हजार किसानों को 198 करोड का अल्पवधि ऋण प्रदान किया गया है। कलेक्टर सिंह ने इस अवसर पर बैंक से सम्बध सहकारी समितियों के पात्र 30 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान नीधि के लाभान्वित, पशु पालन तथा मत्स्य पालन के लिए क्रेडिट कार्ड के प्रमाण-पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम के प्रारम्भ में प्रभारी अवार्ड हरिहर पाण्डे ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश वर्मा, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक हेमेन्द्र रामपुरकर, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. विल्सन डावन, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, प्रभारी उपायुक्त सहकारिता वीसी भिड़े, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।कार्यक्रम का संचालन सुशिला डामोर ने तथा हरिहर पाण्डे ने आभार व्यक्त किया।

कामचोर व रिश्वतखोर कर्मचारी परमार से परेशान दिव्यांग व निराश्रित पेंशनधारी

माही की गूंज, खवासा।

थांदला जनपद में पदस्थ कर्मचारी संजय परमार जिसके पास खाद्यान्न पात्रता पर्ची में नाम जोड़ना व हटाने का कार्य के साथ निराश्रित, दिव्यांग आदि सभी पात्र व्यक्तियों को मिलने वाली पेंशन के कार्य का जिम्मा है पर अगर कोई पात्रता पर्ची में व्यक्ति का नाम जुड़वाने जाए या पात्रता पर्ची संबंधी कोई कार्य हो तो सर्वप्रथम पांच सौ रुपए की रिश्वत की भेंट पहले संजय परमार को चढ़ाना पड़ती है तब जाकर वह अपना कार्य करता है, अगर कोई रिश्वत की भेंट नहीं चढ़ाता है तो उस व्यक्ति का काम कई चक्कर लगाने के बाद भी नहीं करता है।

इसी प्रकार निराश्रित व दिव्यांग लोगों को भी आवेदन एवं सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद भी पात्र व्यक्तियों को पेंशन दिलाने हेतु किए जाने वाले शासकीय कार्यों को अधर में पटक देता है। बताते हैं जनपद में कई बार इसकी सीईओ से शिकायत भी हुई, तो अधिकारी ने भी खुले शब्दों में लंगड़े-लूले का काम अटकाकर कहां जाकर भुगतेगा कह कर डांट-फटकार भी लगाई पर संजय परमार अपनी कार गुजारी से बाज नहीं आता है।

दिव्यांग भामल निवासी नारायण सिंह जवानसिंह पालरा का एक दुर्घटना में एक पैर टूट गया जिससे वह दिव्यांग हो गया, जिसका जिला मेडिकल बोर्ड ने 60 प्रतिशत निःशक्त का प्रमाण पत्र 16 अप्रैल 2018 को जारी किया। तत्पश्चात शासन की योजना के आधार पर पेंशन लेने हेतु दिव्यांग नारायण सिंह ने ग्राम पंचायत भामल के माध्यम से जनपद पंचायत थांदला में आवेदन के साथ वो सारे दस्तावेज दिए जो पेंशन योजना चालू होने के लिए आवश्यक थे परंतु कुछ महीनों के बाद भी पेंशन चालू नहीं हुई तो दिव्यांग ने 2018-19 में ही सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तो जनपद के अन्य कर्मचारी के साथ सीईओ ने भी दिव्यांग से शिकायत वापस ले लो आपकी पेंशन चालू हो जाएगी कहां। सभी के आश्वासन के बाद दिव्यांग ने अपनी शिकायत सीएम हेल्पलाइन से वापस ले ली, परंतु बाबू संजय परमार को दिव्यांग ने पेंशन चालू करवाने हेतु रिश्वत की भेंट नहीं चढ़ाई तो, पेंशन चालु करने की कार्रवाई जनपद स्तर से नहीं की, परेशान होकर फिर इस वर्ष सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में सीएम हेल्पलाइन पर संजय परमार की शिकायत दर्ज की। शिकायत के बाद फिर संजय परमार भामल पंचायत सचिव और झाबुआ का कोई बाबू जिसने दिव्यांग के मोबाइल पर 7974713249 से फोन लगाकर शिकायत सीएम हेल्पलाइन से वापस लेने व पूर्व की तरह फिर से पेंशन चालू करवा देंगे का आश्वासन देकर शिकायत वापस ले लो कि बात कहलवाई पर दिव्यांग ने शिकायत वापस नहीं ली तब जाकर कहीं 18 सितंबर को 6 सौ रुपए पेंशन की राशि दिव्यांग के बैंक खाते में आई।

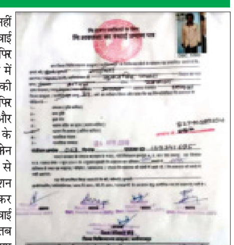

दिव्यांग नारायण सिंह का कहना है कि, संजय परमार बड़ा रिश्वतखोर है अगर मैं सीएम हेल्पलाइन में दूसरी बार शिकायत नहीं करता तो संजय परमार जब तक थांदला जनपद में रहता तब तक मेरी पेंशन चालू नहीं होती, जब भी मैं पेंशन चालू करवाने की बात संजय परमार से करता तो, वह कहता बिना भेंट के कुछ नहीं होता, आपको शिकायत करना हो तो कर दो, मैं राणापुर में जाकर नौकरी कर लूंगा।

अनलॉक शिक्षा के मंदिर, प्राइवेट और सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलें

क्लास नहीं लगेंगी, लेकिन शिक्षकों को रोज जाना होगा, कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध रहेगा

माही की गूंज , रतलाम। राघवेंद्र सिंह डोडिया

मध्यप्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल तो खुल गए है, लेकिन क्लास नहीं लग रही। टीचर से मार्गदर्शन लेने के लिए छात्र पालकों की अनुमति लेने के बाद ही स्कूल जा सकते है, यह आदेश शासकीय और अशासकीय दोनों ही तरह के स्कूलों पर बराबर से लागू हो रहे है। मध्यप्रदेश में शासकीय और प्राइवेट स्कूल 6 महीने बाद 21 सितंबर सोमवार से सिर्फ आंशिक रूप से खुलें है। हालांकि कक्षाएं अभी नहीं लगाई जा रही, लेकिन 9 वीं से 12 वीं तक के छात्र परिजन की अनुमति लेने के बाद थोड़े समय के लिए पढ़ने के लिए आ रहे है, शिक्षकों को अब स्कूल नियमित रूप से आना होगा। प्रदेश में 22 मार्च से ही बच्चों के लिए स्कूल बंद थे। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का सख्ती से पालन करना होगा। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। अभी शिक्षक घर से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। अब उन्हें स्कूल आने की अनिवार्यता कर दी गई है।

यह व्यवस्था थी

प्रदेश में अभी तक की स्थिति में नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक पूरी तरह से 31 सितंबर तक बंद ही हैं। अब तक शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन नए आदेश में 21 सितंबर से सभी शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य है। ऐसे में ऑनलाइन क्लास अब स्कूलों से ही होंगी। राज्य में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संवाद छोटे-छोटे समूह में पर्याप्त समय के अंतराल से हो रहा है।

छह फीट की दूरी रखना जरूरी

स्कूल में एक-दूसरे के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य है। पूरे समय फेस-कवर या मास्क का उपयोग करने के साथ साबुन से बार-बार हाथों को धोना या उन्हें सैनिटाइज करना जरूरी हो गया है। विद्यालय की सभी ऐसी सतहों और उपकरणों का कक्षा शुरू होने और समाप्ति के बाद एक प्रतिशत हाइपो क्लोराइड के उपयोग से डिसइन्फेक्शन (कीटाणु शोधन) करना होगा। स्कूल में केवल कोरोना नेगेटिव व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। विद्यालय में कोविड-19 के निवारक उपायों संबंधी जानकारी भी प्रदर्शित कि जा रही है।

इन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा

कंटेनमेंट जोन में विद्यालय खोलने की अनुमति शासन की ओर से नहीं है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं है। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी, विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक, स्कूल काउंसलर्स और स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम करेंगे। किसी स्कूल में यदि व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो पूरा परिसर सैनिटाइजर किया जाएगा, शिक्षक या कर्मचारी द्वारा बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई होने पर निकटतम चिकित्सा सुविधा संस्थान को तुरंत सूचित करना होता है, उसका चिकित्सीय परामर्श लेना होगा।

इस वर्ष नहीं हो पाएंगे गरबों के आयोजन, रात 8 बजे बंद करनी होंगी दुकानें

माही की गूंज, झाबुआ।

मंगलवार को आपदा प्रबंधन समिति की कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर रोहित सिंह ने नई गाइड लाइन के संबंध में समिति की सदस्यों को जानकारी दी। आने वाले त्योहारों के संबंध में कहा गया किनवरात्र के दौरान गरबों के आयोजन पर रोक लगाई गई है। 6 फीट से बड़ी मुर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी। 10 बाय 10 फीट से बड़ा पांडाल नहीं बनाया जा सकेगा। चल समारोह नहीं निकाले जा सकते है। कोविड-19 के संबंध में उन्होने बताया किफीवर क्लिनिक के माध्यम से अधिक सेंपल लेने पर जोर दिया जाएगा। प्रतिदिन 300 सेंपल जिले में लेने का लक्ष्य रखा गया है।

आने वाली नवरात्र में गरबों के आयोजन नहीं हो पाएंगे। चल समारोह पर भी रोक लगी हैं। अब व्यापारी अपने प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खोल पाएंगे। हॉटल, रेस्टोरेंट अपने निर्धारित समय पर ही बंद किए जाएंगे। रात साढ़े 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी प्रकार के आवागमन पर रोक रहेगी। अन्य कार्यक्रमों में 100 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले पाएंगे। इन कार्यक्रमों में गाइड लाइन का पालन आवश्यक रूप से करना होगा।

फीवर क्लिनिक पर अधिक जोर

कलेक्टर सिंह ने बताया किअब पॉजिटिव पेसेंट के घर पर अगर अलग कमरे व अन्य व्यवस्थाएं रहती है तो उन्हे घर पर ही होम कोरेंटाईन किया जाएगा। किसी मरीज को दिक्कतें है तो उसे कोविड सेंटर ले जाया जाएगा। जिले में पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ ही मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। उन्होने मोबाईल नंबर सार्वजनिक कर मरीजों को इन नंबरों पर संपर्क करने की बात कही। जिले के 8 केंद्रों पर फीवर क्लिनिक बनाए गए है। झाबुआ, रामा, पारा, रानापुर, मेघनगर, थांदला, पेटलावद, कल्याणपुरा स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर मरीज अपना सेंपल दे सकते है। बैठक में रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनोज अरोरा ने ऑक्सीजन स्टूमेट के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा किरोटरी क्लब द्वारा मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए स्टूमेंट उपलब्ध कराए जा रहे है। स्वास्थ्य विभाग इस स्टूमेट का अध्ययन करेगा। बैठक में व्यापारी संघ के अध्यक्षा नीरजसिंह राठौर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्मल मेहता, हिमांशु त्रिवेदी, हर्ष भट्ट, संजय मेहता आदि द्वारा अपने सुझाव दिए गए।

आगामी गाइड लाइन में तय होगा त्योहारों की छूट

बैठक में कई सदस्यों ने दशहरा पर्व व दीपावली को लेकर प्रश्न किए थे। जिस पर कलेक्टर सिंह ने कहा किफिलहाल नवरात्र को लेकर गाइड लाइन आई है। आगामी गाइड लाइन आने पर ही दशहरा व दीपावली पर्व को लेकर कुछ कहा जा सकता है। उन्होने आम जनता से आव्हान किया किप्रदेश सरकार की गाइड लाइन का पालन करें व सावधानी बरतें। बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

संपादकीय

सत्ता पक्ष और विपक्ष को चाहिए किसानों का साथ, एकजुटता से होगा किसानों का फायदा

राज्यसभा में कृषि विधेयकों के विरोध में जो हुआ, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में विरोध की एक सीमा है, विरोध जताने के तय संसदीय पैमाने हैं, लेकिन लगता है, कई बार कुछ सांसद इसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। जिस तरह से विरोधी सांसदों ने राज्यसभा के वेल में आकर प्रदर्शन किया और उप-सभापति के साथ जो व्यवहार किया, उसे सिवाय कोरी राजनीति के कुछ नहीं कहा जा सकता। नियम पुस्तिका फाड़ने या तोड़फोड़ की कोशिश को देश ने देखा है, जिससे राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्यों की चमक और फीकी हुई है। जिस तरह से राज्यसभा में कृषि संबंधी विधेयकों को पारित होने से रोकने की कोशिश हुई थी, उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने आठ सांसदों को निलंबित कर दिया है। जिन विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है, उनमें तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन व डोला सेन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव सातव, सैयद नासिर हुसैन, रिपुन बोरा और सीपीआई (एम) से के के रागेश व एल्मलारान करीम के नाम हैं।

निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं, इस पर विशेषज्ञों में बहस चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से उप-सभापति के सामने दुर्व्यवहार किया गया, उसे गलत मानने वालों की संख्या आज ज्यादा है। अगर किसी विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए कोई बल का प्रयोग करता है, कुछ फाड़ने-तोड़ने की कोशिश करता है, तो इस परंपरा को तत्काल रोकने की जरूरत है। देश के ऊपरी सदन राज्यसभा के वरिष्ठ सांसदों को अपनी गरिमा और विरोध शैली का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सड़क और संसद में संघर्ष का तरीका अलग होना ही चाहिए। इसमें एक पक्ष यह भी है कि संसद में इस तरह की उत्तेजना पहले भी पैदा होती रही है, और निलंबन की परंपरा को आगे बढ़ाने से पहले विचार कर लेना चाहिए। आश्वासन लिया जा सकता है कि दोषी सांसद फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, मगर सुलह-सफाई की कोशिश फिलहाल नहीं दिखती है, तो मामला राष्ट्रपति तक जाएगा। कृषि संबंधी विधेयक को कानून बनने और लागू होने से रोकने के लिए कुछ विपक्षी दल सक्रिय रहेंगे। ध्यान देने की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने उप-सभापति हरिवंश के साथ हुए व्यवहार को बिहार के अपमान से जोड़ दिया है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और संभव है, वहां यह मुद्दा बना रहे।

कुल मिलाकर, इस विवाद को बढ़ाने की बजाय समाधान निकालना चाहिए। अगर किसान देश की सड़कों पर लामबंद होते हैं, तो आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के लिहाज से भी स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। यह किसानों की मजबूती ही है कि कोई भी दल उनके समर्थन को गंवाना नहीं चाहेगा। यदि विपक्षी दलों में विरोध की बेचैनी है, तो सत्तारूढ़ दल में किसानों को साथ रखने की कवायद है। जो संभावनाएं दिख रही हैं, उसमें इस पूरी किसान राजनीति से किसानों को फायदा ही होता दिखता है। मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कवच पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आ सकता है। पर यह भी देखना चाहिए कि कुछ राज्य हैं, जहां मंडी व न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था नहीं है। आज हर राज्य के हर अन्नदाता की रक्षा के उपाय जरूरी हैं और यह बात जितनी सत्ता पक्ष पर लागू होती है, उतनी ही विपक्ष पर भी।

स्कूली शिक्षा की वैकल्पिक राहें

गिरीश्वर मिश्र

स्कूली शिक्षा सभ्य बनाने के लिए एक अनिवार्य व्यवस्था बन चुकी है। शिक्षा का अधिकार संविधान का अंश बन चुका है। भारत में स्कूलों पर प्रवेश के लिए बड़ा दबाव है और अभी करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो स्कूल जा रहे हैं उनमें से काफी बड़ी संख्या में बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। यानी शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। बच्चों को उनकी रुचि, क्षमता और स्थानीय सांस्कृतिक प्रासंगिकता आदि को दरकिनार रख सभी को एक ही ढाँचे में एक ही तरह के सांचे में ढाल कर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सरकार की औपचारिक शिक्षा प्रणाली फैक्ट्री में थोक के हिसाब से माल तैयार करने के तर्ज पर एक ही तरह के मानक की पक्षधर है।

मनुष्य मात्र में जन्म से ही दिखने वाली व्यक्तिगत भिन्नता के तथ्य की अनदेखी करते हुए और मानवीय प्रतिभा की सृजनात्मकता और स्वतन्त्र चिंतन की नैसर्गिक विशेषताओं को भुलाकर सबके लिए एक ही पैमाने का उपयोग व्यवस्था की दृष्टि से सुभीता तो जरूर देता है पर सहज मानसिक विकास में बाधक होता है। कुल मिलाकर मुख्यधारा के स्कूलों को लेकर काफी असंतोष देखने को मिलता है। शिक्षा में जिस खुलेपन और विविधता की जरूरत होती है उसके लिए विद्यालय की संस्था को अधिक संवेदनशील और आग्रहमुक्त होने की जरूरत है। वैसे भी विश्व की अनेक प्रतिभावान विभूतियों ने स्कूल की संस्था की उपादेयता पर प्रश्नचिह्न उठया है। स्कूलों की संस्था की उपयोगिता के विवाद में न भी पड़ें तो स्कूलों में विविधता इसलिए भी जरूरी है कि स्कूली आयु के बच्चे न केवल सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अनेक तरह की पृष्ठभूमियों से आते हैं बल्कि उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, स्कूल के लिए तत्परता और शारीरिक-मानसिक क्षमता (जैसा दिव्यांग बच्चों में मिलता है) और जटिल सामाजिक पारिवारिक परिवेश में भी अंतर पाए जाते हैं। कुंठा के चलते स्कूल छोड़कर चले जाने वाले बच्चों और युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। देश अभी भी पूर्णतरू साक्षर नहीं हो सका है। ऐसे में वैकल्पिक स्कूलों की व्यवस्था का महत्त्व बढ़ जाता है।

आधुनिक भारत में प्रचलित स्कूली व्यवस्था एक ओर अपने औपनिवेशिक अतीत से बंधी है तो दूसरी ओर अब उसपर वैश्विकता का भूत सवार है। इन सबके बीच यथास्थिति बनी हुई है- न ययौ न तस्थौ। इनको अपर्याप्त मानते हुए वैकल्पिक स्कूल को लेकर कई प्रयास होते रहे हैं। पाठशाला, गुरुकुल और मदरसे तो जमाने से चले आ रहे थे। अंग्रेजों के जमाने में नया ढांचा चला जो अब मुख्यधारा बना हुआ है। गांधीजी ने शिक्षा के सुन्दर वृक्ष के समूल विनाश के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया था परन्तु 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी प्रतियोगिता और उपभोक्तावाद के आगोश में हम उसी शिक्षा पद्धति को चलाते रहे। इससे सामाजिक असमानता भी बढ़ी और मूल्यों की दृष्टि से भी हम कमजोर पड़ते गए। इसके समानांतर महंगे निजी स्कूलों की भी भरमार हो गई।

वैकल्पिक दृष्टि से स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद ने प्रयास शुरू किया था। महात्मा गांधी, गुरुदेव रबीन्द्र नाथ टैगोर, श्री अरविन्द, गीजू भाई बधेका, जिद्दू कृष्णमूर्ति के शैक्षिक प्रयासों से नए तरह के स्कूल के प्रयोग शुरू हुए। चिन्मय मिशन, साधू वासवानी ट्रस्ट, दयालबाग शैक्षिक संस्थान आदि भी इस दिशा में कार्यरत हैं। ऐसे ही मांटेसरी पद्धति के विद्यालय भी चल रहे हैं। सत्तर के दशक में होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, बंगलोर का विकासना, राजस्थान में दिगंतर, उत्तराखंड में सिद्ध स्कूल, मध्य प्रदेश में आधारशिला शिक्षण केंद्र, तमिलनाडु में विद्योदय स्कूल, बिहार में चरवाहा विद्यालय जैसे प्रयासों के साथ ही पूरे देश में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान भी इस दिशा में कई नवाचारी प्रयास कर रहा है।

इन वैकल्पिक स्कूलों के विचारों और अभ्यासों को आत्मसात कर मुख्यधारा की शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकेगा। भारत में नवाचारों के लिए प्रतिरोध आम बात है। माता-पिता, अभिभावक, नीति निर्माता, अध्यापक सभी चाहते हैं कि सुधार हो परन्तु यह सरल नहीं होता है। हम विकल्प के स्कूल के रूप में जिन संस्थाओं को पाते हैं वे प्रायरू उन सीमाओं को लांघने की कोशिशें हैं, जिनसे उबरने के लिए मुख्यधारा की संस्थाएं जूझ रही हैं। वैकल्पिक स्कूल शिक्षा के उन्नयन की राह दिखाते हैं। इनमें बच्चे स्वयं अपनी प्रतिभा और रुचि को तलाशते हुए आगे बढ़ते हैं। इस काम में अध्यापक, माता-पिता, हित मित्र सहायक का काम करते हैं। सीखना अपने आसपास के पूरे परिवेश के बीच और परिवेश के माध्यम से होता है। ज्ञान, कौशल और मूल्यों की बच्चे की अपनी चाह को आदर देते हुए वैकल्पिक स्कूल परीक्षा, प्रतिष्ठा और पद की लालसा के बदले सीखने की सामर्थ्य पर बल देते हैं। इनमें बच्चा या विद्यार्थी ही केंद्र में होता है। सीखने और सिखाने की कोई एक मानक शैली न होकर उसकी कई राहें खुली होती हैं। इन स्कूलों में ज्ञान के विषयों की सीमाएं आपस में मिलती हैं और उनके आपसी रिश्तों की पड़ताल की जाती है। सीखते हुए और खेलकूद, संगीत और कल्पनाशीलता के लिए अवसर मिलने से बच्चे की संवेदना का भी विस्तार होता है। जीवन को समृद्ध करने वाले आध्यात्मिक, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के साथ दायित्वों को जीवन में उतारने की कोशिश इन स्कूलों की खास विशेषता होती है। लोकतांत्रिक और लचीले प्रशासन के बीच संचालित होने वाले इन स्कूलों में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और उनके हुनर विकसित करने की भी व्यवस्था होती है।

वैकल्पिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और उनमें ऐसा बहुत कुछ है जो मुख्यधारा के लिए प्रासंगिक और उपयोगी है। देश के लिए विकसित हो रही नई शिक्षा नीति में भी वैकल्पिक स्कूली शिक्षा को समर्थ बनाने की बात कही गई है। जरूरी है कि इस तरह के वैकल्पिक स्कूल से उन तत्वों को ग्रहण किया जाय जिनसे शिक्षा की मुख्यधारा को उस कैद से आजाद किया जाय जिनके चलते सीखने की जगह परीक्षा और कौशल की जगह प्राप्तांक को तरजीह मिलाती है।

(लेखक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विवि, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

पाक में सरकार के ऊपर सरकार

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने लगभग सभी प्रमुख विरोधी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तानी फौज की कड़ी आलोचना की गई। पाकिस्तानी फौज की ऐसी खुलेआम आलोचना करना तो पाकिस्तान में देशद्रोह-जैसा अपराध माना जाता है। नवाज शरीफ ने अब इस फौज को नया नाम दे दिया है। उसे नई उपाधि दे दी है। फौज को अबतक पाकिस्तान में और उसके बाहर भी श्सरकार के भीतर सरकारश् कहा जाता था लेकिन मियां नवाज ने कहा है कि वह श्सरकार के ऊपर सरकारश् है। यह सत्य है।

पाकिस्तान में अयूब खान, याह्या खान, जिया-उल-हक और मुशर्रफने अपना फौजी शासन कई वर्षों तक चलाया ही लेकिन जब गैर-फौजी नेता लोग सत्तारुढ़ रहे, तब भी असली ताकत फौज के पास ही रहती चली आई है। अब तो यह माना जाता है कि इमरान खान को भी जबर्दस्ती जिताकर फौज ने ही पाकिस्तान पर लादा है। फौज के इशारे पर ही अदालतें जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफऔर गिलानी जैसे नेताओं के पीछे पड़ती रही हैं। ये ही अदालतें क्या कभी पाकिस्तान के बड़े फौजियों पर हाथ डालने की हिम्मत करती हैं? पाकिस्तान के सेनापति कमर जावेद बाजवा की अकूत संपत्तियों के ब्यौरे रोज उजागर हो रहे हैं लेकिन उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। मियां नवाज ने कहा है कि विपक्ष की लड़ाई इमरान खान से नहीं है, बल्कि उस फौज से है, जिसने इमरान को गद्दी पर थोप रखा है।

यहां असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के नेता लोग फौज से लड़ पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि फौज थोड़ी पीछे खिसक जाए। सामने दिखना बंद कर दे, जैसा कि 1971 के बाद हुआ था या जैसा कि कुछ हद तक आजकल चल रहा है लेकिन फौज का शिकंजा पाकिस्तानियों के मन और धन पर इतना मजबूत है कि उसे कमजोर करना इन नेताओं के बस में नहीं है।

पाकिस्तान का चरित्र कुछ ऐसा ढल गया है कि फौजी वर्चस्व के बिना वह जिंदा भी नहीं रह सकता। यदि पंजाबी प्रभुत्ववाली फौज कमजोर हो जाए तो पख्तूनिस्तान और बलूचिस्तान टूटकर अलग हो जाएंगे। सिंध का भी कुछ भरोसा नहीं।1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तानी जनता के मन में भारत-भय इतना गहरा पैठ गया है कि उसका एकमात्र मरहम फौज ही है। फौज है तो कश्मीर है। फौज के बिना कश्मीर मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। इसके अलावा फौज ने करोड़ों-अरबों रु. के आर्थिक व्यापारिक संस्थान खड़े कर रखे हैं। जबतक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का मूल चरित्र नहीं बदलेगा, वहां फौज का वर्चस्व बना रहेगा।

(लेखक सुप्रसिद्ध पत्रकार और स्तंभकार हैं।)

चाणक्य नीति

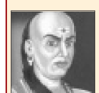

उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगो को बड़े पैमाने पर भोजन ना कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को ख़तम कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण ना करे तो यज्ञ उसे ख़तम कर देता है। और यदि यजमान लोगों को दान एवं भेटवस्तू ना दे तो वह भी यज्ञ द्वारा ख़तम हो जाता है।

काम की बात

अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नही चमकते।

एक सलाह

फर्क सिर्फ सोच का होता है, सकारात्मक या नकारात्मक। वरना सीढ़ियां वही होती है, जो किसी के लिए ऊपर जाती है और किसी के लिए नीचे आती है।

चीन तनाव को लेकर संसद में चर्चा क्यों नहीं?

डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

युद्ध न चाहते हुए भी भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं एलएसी के पास बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना पक्ष मजबूत बताते हुए खड़ी हैं। तनाव चरम पर है। बाहर से देखने पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है लेकिन युद्ध की विभीषिका और उसके नतीजों की आशंका में दोनों देशों के कूटनीतिज्ञ अपने स्तर से युद्ध की स्थिति को खत्म कर दोनों देशों के बीच समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं।

चीन किसी भी प्रकार की समस्या को पारदर्शी ढंग से सबके समक्ष रखने और उससे जन-जन को अवगत कराने का पक्षधर कभी नहीं रहा। बड़ी-बड़ी समस्याओं के संदर्भ में भी चीन सदैव मौन रहता है, वह देश के समक्ष कोई भी तथ्य नहीं रखता। इसके विपरीत भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण नीतियों में पारदर्शिता और हर समस्या के विभिन्न पहलुओं से जनता को भी अवगत कराना सरकार की लोकतांत्रित जिम्मेदारी भी है। चीन, पाकिस्तान जैसे कम्युनिस्ट तानाशाही या फौजी शासन व्यवस्था में प्रायः इसका अभाव देखा जाता है।

इस समय भारत-चीन के बीच गंभीर तनाव को लेकर सरकार पर्याप्त गोपनीयता बरत रही है जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस संसद में इस मुद्दे पर चर्चा चाहती है। हालांकि सत्ता पक्ष को कांग्रेस की यह मांग स्वीकार नहीं है और सरकार इसपर संसद में चर्चा कराने के पक्ष में नहीं है। यहां यह प्रश्न उठता है कि सरकार सीमा पर आखिर चीन की उपस्थिति को लेकर इतनी गोपनीयता क्यों बरत रही है और इसपर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार क्यों नहीं है?

वैसे तो किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग विपक्षी दलों का अधिकार और उसपर चर्चा सरकार का दायित्व है। किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जहां एक ओर प्रतिद्वंद्वी चीन जैसा धूर्त हो तो हर कदम पर सतर्कता आवश्यक है। रीति-नीति और अपनी तैयारियों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सरकार सदन में इसकी चर्चा के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष की मांग को देखते हुए सरकार राजनीतिक दलों से अलग-अलग मिलकर उन्हें यह समझाने का प्रयास कर रही है कि इसपर सदन में चर्चा उचित है। प्रायः सभी राजनीतिक दल सरकार के मत से सहमत भी हो रहे हैं किंतु कांग्रेस पूरी आक्रमकता के साथ अपनी इस मांग पर अड़ी है।

शिवसेना ने भले ही संसद के बाहर इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफबयान दिया मगर संसद में इसकी भूमिका आक्रामक नहीं है। सपा, बसपा, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, बीजेडी जैसे दलों ने न तो आक्रामक रुख अख्तियार किया और न इसपर चर्चा की मांग की है। वस्तुतः राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सैन्य प्रशासन तथा उसकी गतिविधियों से संबंधित प्रकरण पूर्ण गोपनीयता की अपेक्षा रखते हैं। गोपनीय बने रहने पर ही वह विपक्षी देश के लिए चुनौती बन पाते हैं अन्यथा शत्रु देश किसी भी तैयारियों पर पानी फेर सकता है। प्रायः हर देश अपने शत्रु सेनाओं की क्षमताओं, गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी अपने गुप्तचरों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता और विपक्षी दल इस तथ्य से परिचित हैं इसलिए संसद में इसपर चर्चा कराने के लिए कहीं से भी जोरदार मांग नहीं उठ रही है।

1962 में चीन के साथ युद्ध में कम्युनिस्टों द्वारा की गयी चीन की पक्षधरता की तरह इस समय कांग्रेस चीन का मुखर पक्षधर प्रतीत हो रही है। सरकार की ओर से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भारत-चीन तनाव को लेकर बात रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को जोरदार ढंग से रखा। इससे कांग्रेस सहित दूसरे राजनीतिक दल भी सरकार के साथ नजर आए। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सररकार ने पूरी गोपनीयता बनाए रखी जिससे सैन्य गतिविधियों और तैयारियों को लेकर किसी को भनक नहीं लगी। इसके चलते इसबार पहली बार चीन भारत को धमकाने की बजाय नरम तेवर के लिए मजबूर हुआ। भारतीय सेना द्वारा अपनी योजनाओं को प्रकट नहीं होने देकर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ ऊंची-ऊंची चोटियों पर कब्जा जामकर बैठ जाना ही चीन की इस नरमी की वजह है। यदि किसी माध्यम से सरकार तथा सेना की इस योजना की जानकारी चीन तक पहुंच गयी होती तो निश्चित तौर पर ब्लैक टॉप एवं पैंगोलिन झील के किनारे स्थित अनेक फिंगर चोटियों पर कब्जा जमाना उसके लिए असंभव हो जाता और चीन इस क्षेत्र में बढ़त बनाकर रखते हुए पूर्व की तरह भारत को धमका रहा होता।

जहां तक संसद में इसपर चर्चा का प्रश्न है, मौजूदा स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सैन्य योजनाओं पर खुलकर चर्चा नहीं हो सकती। गोपनीयता बनाए रखकर उसपर अमल कर खुद को मजबूत बनाए रखना, आज की जरूरत है। इसके बल पर बिना युद्ध किए कूटनीतिक स्तर पर वार्ता कर समस्या का समाधान करते हुए चीन को झुकाया जा सकता है। हमें यह बात सदैव याद रखनी होगी कि 1962 में चीन हिंदी-चीनी भाई-भाई के नारे की आड़ में भारत के साथ छल किया। हमारी तत्कालीन कमजोरी और अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन ने अक्साई चीन की लगभग 40000 वर्ग किमी भूमि हथिया ली, जिसे वापस पाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेना की आवश्यकताओं की हर प्रकार की पूर्ति कर उसकी शक्ति तथा गतिविधियों को मजबूती प्रदान करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

प्रतिबद्धता का भय- अंतिम

संबंधों में शांति पूर्वक रहना बहुत कठिन है। लेकिन वही चुनौती है। यदि तुम उससे बचते हो तो तुम परिपक्वता से वंचित रह जाओगे। यदि तुम समूची पीड़ा के साथ उसमें उतरोगे, और फिर भी उसमें जाते रहोगे तो धीरे-धीरे वह पीड़ा एक आशीष बन जाती है, अभिशाप वरदान बन जाता है। धीरे-धीरे संघर्ष के द्वारा, घर्षण के द्वारा केंद्रीकरण होता है।उस संघ के द्वारा तुम अधिक सजग, अधिक सावचेत हो जाते हो।दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए आईना बन जाता है। तुम अपनी कुरूपता दूसरे में प्रतिफलित हुाई देख सकते हो। दूसरा तुम्हारे अचेतन को उकसाता है, उसे सतह पर लाता है। तुम्हें अपने अंतरतम के सभी छुपे हुए हिस्सों को जानना होगा, और उसका सबसे आसान तरीका है प्रतिफलित होना, संबंध के दर्पण में झांकना। मैं इसे सरल कहता हूं क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है लेकिन है यह बहुत दूभर, कठिन क्योंकि इसके द्वारा खुद को बदलना होगा।

जब तुम सद्गुरु के पास आते हो तब तो इससे भी बड़ी चुनौती खड़ी होती है, तुम्हें निर्णय लेना होता हैय और निर्णय अज्ञात के पक्ष में लेना होता है और निर्णय समग्र और अंतिम होता है, अपरिवर्तनीय होता है। यह बच्चों का खेल नहीं है, यह वापिस न लौटने का बिंदु है।इतना संघर्ष होता है। लेकिन लगातार बदलते मत रहो क्योंकि यह खुद से बचने का उपाय है। और तुम कोमल रहोगे, तुम बचकाने रहोगे, परिपक्व नहीं होओगे। केवल अज्ञात ही तुम्हें आकर्षित करे क्योंकि उसे तुमने अभी तक जीया नहीं है, उस क्षेत्र में तुम गए नहीं हो। वहां जाओ! वहां कुछ नया घट सकता है। हमेशा नए के हक में निर्णय लो-- चाहे जो भी जोखिम हो, और तुम सतत विकसित होओगे। और ज्ञात के पक्ष में निर्णय लो तो तुम अतीत के साथ एक वर्तुल में घूमते रहोगे। तुम दोहराते रहोगे, तुम एक ग्रामोफोन रिकार्ड बन गए हो।

और निर्णय लो। जितने जल्दी निर्णय ले सको उतना अच्छा। स्थगित करना बिलकुल मूढ़ता है। कल भी तुम्हें निर्णय लेना ही होगा, तो आज ही क्यों नहीं? और क्या तुम ऐसा सोचते हो कि कल तुम आज से ज्यादा समझदार होओगे?क्या तुम सोचते हो कि कल तुम आज से ज्यादा जीवंत होओगे? क्या तुम सोचते हो कि कल तुम आज से अधिक जवान और ताजा होओगे? कल तुम ज्यादा बूढ़े हो ओगे, तुम्हारा साहस कम होगा, तुम अधिक अनुभवी हो ओगे, तुम्हारी चालाकी अधिक होगी। कल मौत अधिक पास आएगी, तुम कंपना शुरू करोगे और भयभीत होओगे। कल के लिए कभ स्थगित मत करना। किसे पता, कल आए न आए! अगर निर्णय लेना ही है तो अभी लेना होगा।

कृषि बिल और गफलत

राज्यसभा में रविवार को केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े दो बिल फार्मर्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) बिल और फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल ध्वनिमत से पास करा लिया। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएंगे। इससे पहले वोटिंग के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर जमकर नारेबाजी की। तृणमूल सांसद डेरेक ओ्यब्रायन ने उपसभापति हरिवंश का माइक तोडने की कोशिश की। उन्होंने सदन की रूल बुक फाड़ दी। सदन की कार्यवाही जारी रखने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से दोनों बिल पास होने के बाद 8 ट्वीट किए। किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने एक बार फिर से किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी और सरकारी खरीददारी पहले की तरह जारी रहेगी। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समाप्त करने और कॉरपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए दोनों नए कृषि विधेयक लेकर आई है। हालांकि सरकार ने इसका खंडन करते हुए कहा कि किसानों को बाजार का विकल्प और उनकी फसलों को बेहतर कीमत दिलाने के उद्देश्य से ये विधेयक लाए गए हैं।

जो भी हो, सरकार और विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वह सब भविष्य के गर्भ में है। सरकार की बात सच होगी या विपक्ष की, यह सामने आएगा। मगर अभी सरकार जो कह रही है, उस पर भरोसा करना होगा। सरकार का कहना है कि एमएसपी का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी खरीद जारी रहेगी तो ऐसा होगा।

एमएसपी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े। उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। सरकार हर फसल सीजन से पहले सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती है, तब एमएसपी उनके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइज का काम करती है। यह एक तरह से कीमतों में गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो एमएसपी का गणित पता चलेगा। 1950 और 1960 के दशक में किसान परेशान थे। यदि किसी फसल का बंपर उत्पादन होता था, तो उन्हें अच्छी कीमतें नहीं मिल पाती थी। इस वजह से किसान आंदोलन करने लगे थे। 1964 में एलके झा के नेतृत्व में फूड-ग्रेन्स प्राइज कमेटी बनाई गई थी। झा कमेटी के सुझावों पर ही 1965 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की स्थापना हुई और एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन (एपीसी) बना। इन दोनों संस्थाओं का काम था देश में खाद्य सुरक्षा का प्रशासन करने में मदद करना। एफसीआई वह एजेंसी है जो एमएसपी पर अनाज खरीदती है। उसे अपने गोदामों में स्टोर करती है। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के जरिये जनता तक अनाज को रियायती दरों पर पहुंचाती है। पीडीएस के तहत देशभर में करीब पांच लाख उचित मूल्य दुकानें हैं जहां से लोगों को रियायती दरों पर अनाज बांटा जाता है। एपीसी का नाम 1985 में बदलकर सीएपीसी किया गया। यह कृषि से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों को तय करने की नीति बनाने में सरकार की मदद करती है।

सिद्धार्थ शंकर

संतों को समझना आसान नही

डॉ.अर्चिका

नानक देव के पुत्र थे ''श्री चन्द'' देखने में साधारण, वस्त्र भी सामान्य, कहीं भी बैठ जाते, किसी साधारण से साधारण के साथ घुल जाते। जंगल में वर्षों तक प्रारम्भिक दौर की साधना करने के दौरान एक दिन उनके मन में गुड़ खाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने शिष्य से कहा आत्म स्वरूप, जाओ कस्बे से थोड़ा गुड़ ले आओ। गुड़ खाने का मन है।

शिष्य गुड़ के एक बहुत बड़े व्यापारी के पास जाकर कहने लगा हमारे गुरुदेव के आश्रम के लिए थोड़ा सा गुड़ दे दो। यह सुनते ही सेठ ने भड़ककर कहा बोहनी का समय है, सुबह-सुबह माँगने आ गये। यदि सुबह-सुबह तुम्हें मुफ्त में दे दिया, तो सारा दिन खराब हो जाएगा। इसके बावजूद शिष्य बार-बार निवेदन करने लगा कि आपके तो इतने सारे गोदाम हैं, थोड़ा गुड़ हमारे गुरुदेव के लिये दे देंगे, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। सेठ जी बोले अरे आगे जाओ, यहां कोई गोदाम नहीं है। इस गोदाम में मिट्टी भरी है।

यह सुनकर शिष्य बिना गुड़ के ही श्री चन्द्र जी के पास वापस चले गये और जाकर सद्गुरु से कहा गुरुदेव एक ही जगह गया था और उस आदमी ने गुड़ देने से मना कर दिया। जब मैंने कहा तुम्हारा इतना बड़ा गोदाम है, तो उसने बोला, वो तो सब मिट्टी भरी है।

गुरु बोले अच्छा स्वरूप बैठ जाओ। मेरे मन में अब गुड़ की चाह नहीं है। पर शिष्य अभी शांत नहीं हो पाया था, उसने अपने गुरु से कहा- उसके गोदाम में तो गुड़ ही गुड़ है, फिर उसने ऐसा क्यों कहा। श्री चन्द जी बोले हो सकता है वह सच कह रहा हो, हो सकता है उसके पास मिट्टी ही हो। इस वाकिया के अभी कुछ ही समय बीता था कि सेठ के गोदाम में कहीं से पानी अंदर आ गया और गोदाम का सारा गुड़ खराब हो गया, कीचड़ भरने के कारण सारा गुड़ वास्तव में मिट्टी बन गया। सेठ के गोदाम का गुड़ मिट्टी बनने की खबर पूरे शहर भर में फैल गयी। सेठ भी गुड़ न देने की बात बड़बड़ा रहा था। लोग भागते हुए महात्मा श्री चन्द से कहने लगे प्रभु! आपकी वाणी से उस बेचारे का बहुत बुरा हुआ, यह सुनकर श्री चन्द को भी बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, स्वरूप उठो अब यहां नहीं रहना। लगता है! भगवान का नाम जपते-जपते इस जुबान में शक्ति आ गयी और यह जुबान दुनिया के व्यवहार के लायक नहीं रही। उसका परिणाम कितना बुरा हुआ? लोगों ने श्री चन्द को लाख मनाया पर वे नहीं रुके।

कृषि कानूनों का विरोध कितना वाजिब

अनिल निगम

राजनीतिक दल सोची-समझी रणनीति के तहत किसानों से संबंधित तीन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर था कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर दिया है। अकाली दल की नेत्री हरसिमरत बादल का केन्द्रीय मंत्री पद से इस्तीफा एक राजनीतिक चाल है। अकाली दल पंजाब में अपने घटते जनाधार से बेहद चिंतित है। इसलिए उन्होंने इस इस्तीफे से पंजाब के किसानों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अकाली दल उनका हितैषी है।

पंजाब और हरियाणा किसानों के गढ़ हैं। सबसे ज्यादा फसल पंजाब में उगती है। कुछ पंजाबी किसान संगठनों ने इन तीनों कानूनों को किसान-विरोधी बताया है और वे इनके विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं। कुछ दूसरे प्रदेशों में भी विरोधी दलों के उकसावे पर किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया अथवा ऐसा करने की योजना बना रहे हैं।

निस्संदेह, तीनों कानून किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। पहला कानून किसान का उत्पाद, व्यापार एवं विपणन, दूसरा- आवश्यक अधिनियम 1955 में संशोधन और तीसरा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बनाया गया है। पूर्व में प्रावधान था कि देश के किसान अपनी फसल बेचने के लिए अनिवार्य रूप से अपनी स्थानीय मंडियों में जाएं और दलालों-आढ़तियों की मदद से अपना खाद्यान्न बेचें। लेकिन अब उनके ऊपर से ये बाध्यता समाप्त हो जाएगी। अब वे अपना माल सीधे बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं। कहने का आशय यह है कि किसानों के लिए अब पूरा देश खुल गया है। उनकी निर्भरता मंडियों और आढ़तियों पर खत्म हो जाएगी। जब किसान अपनी फसल स्थानीय मंडियों में बेचते थे तो उनको आढ़तियों या दलालों को कमीशन देना पड़ता था। लेकिन उक्त कानून लागू होने के बाद उनको न मंडी-टैक्स देना पड़ेगा और न ही आढ़तियों को कमीशन। चूंकि अब वे अपने माल को देश की किसी भी मंडी या व्यापारी को बेचने को स्वतंत्र होंगे, इसलिए उन्हें फसल की कीमतें ज्यादा मिलेंगी।

इसके बावजूद कुछ विपक्षी दलों ने किसानों को उकसाया कि नए कानून पूरी तरह से किसान विरोधी हैं और इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तर्क दिया गया कि फसल अब औने-पौने दामों पर बिका करेगी, क्योंकि बाजार तो बाजार है। बाजार में दाम उठते-गिरते रहते हैं। परन्तु मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से किसानों की अधिक सुरक्षा रहती है। किसानों के इस डर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य हर हाल में मिलेगा। इसको सरकार समाप्त नहीं करेगी।

भारत में आज भी 50 फीसदी से अधिक आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। लेकिन भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान सिर्फ18 फीसदी योगदान है। यह अत्यंत विचारणीय बिंदु है। पिछले वर्ष किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 10.07 करोड़ किसानों में से 52.5 प्रतिशत कर्ज में दबे हुए हैं। वर्ष 2017 में एक किसान परिवार की कुल मासिक आय 8,931 रुपये थी। वास्तव में किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वे बिचौलियों की मर्जी पर निर्भर हैं। हर किसान को खुला बाजार मिलने से उन्हें अपना माल बेचने की आजादी होगी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कुछ राजनीतिक दल किसानों को एक पक्षीय तस्वीर दिखा रहे हैं।

सरकार की मंशा किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने की है। यह कानून किसानों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। हालांकि इस बात का खतरा जरूर है कि उनकी फसलों पर देश के बड़े पूंजीपति अग्रिम कब्जा कर बाजार में ज्यादा महंगा बेचने लगें। ऐसा भी संभव है कि वे किसानों को अग्रिम पैसा देकर फसलों की खरीददारी पहले ही सुनिश्चित कर लें। यह खतरा तो रहेगा। पर इसमें भी फायदा किसानों का ही होगा। इस नई व्यवस्था में किसानों का कोई अहित न होने पाए, इसके लिए सरकार एक सशक्त मॉनिटरिंग सिस्टम अवश्य बनाना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

समय की मांग है 'ऑनलाइन वोटिंग'

प्रभुनाथ शुक्ल

ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था वर्तमान समय की मांग है। आधुनिक तकनीक और विकास की वजह से वोटिंग के दूसरे तरीके भी अब मौजूद हैं। वैसे इसे हैक की आशंका से खारिज नहीं किया जा सकता है। वोटरों को सीधे आधारकार्ड से जोड़ कर मतदान की आधुनिक सुविधा प्रणाली विकसित की जा सकती है।आज का दौर आधुनिक है और हर वोटर के हाथ में एंड्रायड मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है। आयोग वोटिंग ऐप लांच कर नई वोटिंग प्रणाली का आगाज कर सकता है। आधार जैसी सुविधाओं का हम दूसरी सरकारी योजनाओं में उपयोग कर सकते हैं, फिर वोटिंग के लिए आधार प्रणाली का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता है।

भारत में आज भी लाखों लोग चाह कर भी अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देश के अधिकांश लोगों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। वोटिंग प्रणाली को सीधे अंगूठे से अटैच किया जाए। जिस तरह से दूसरी सरकारी योजनाओं में आधार का उपयोग किया जा रहा है उसी तरह वोटिंग में भी इसका उपयाग होना चाहिए। इस व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति सीधे अपने अंगूठे का प्रयोग कर मतदान कर सकता है।मोबाइल ऐप के जरिए भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बगैर वोटिंग बूथ तक पहुंचे कर सकते हैं। इससे चुनाव और सुरक्षा पर होने वाला करोड़ों रुपये का खर्च बचेगा। ईवीएम मशीनों के विवाद और इस्तेमाल के अलावा रख रखाव से निजात मिलेगी। वोटिंग की तारीख किसी विशेष इलाके के आधार पर निर्धारित करने के बजाय कम से कम 30 दिन तक निर्धारित की जाए।हालांकि यह तकनीक बेहद उलझाव भरी होगी, क्योंकि वोटिंग विधान और लोकसभा के आधार पर की जाएगी। उसी के आधार पर वोटिंग ऐप और दूसरी सुविधाएं लांच करनी पड़ेगी।

ऑनलाइन वोटिंग में तमाम तरह की समस्याएं भी आएंगी। इसमें काफी लंबा वक्त भी लग सकता है। हैकरों की तरफसे इसे हैक किए जाने की कोशश भी की जा सकती है। लेकिन अगर आयोग चाहेगा तो यह बहुत कठिन नहीं होगा। तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर इसे आसान बनाया जा सकता है।भारत निर्वाचन आयोग बेहद विश्वसनीय संस्था है। उसे अपना यह भरोसा कायम रखना होगा। हालांकि विपक्ष के आरोपों में बहुत अधिक गंभीरता नहीं दिखती है। लेकिन अगर सवाल उठाया गया है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। सत्ता और प्रतिपक्ष का अपना-अपना धर्म है। राजनीति से परे उठ कर सभी संस्थाओं को अपने दायित्वों का अनुपालन करना चाहिए, जिससे लोकतंत्र की तंदुरुस्ती कायम रहे।

चुनाव आयोग ईवीएम मशीन की सुचिता बनाए रखने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। लेकिन आपको याद होगा कि मध्यप्रदेश के भिंड में परीक्षण में इसकी हवा निकल गई थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार को जाने वाला वोट दूसरे पार्टी को चला गया था। जिसके बाद आयोग की खूब किरकिरी हुई थीं। वीवीपैट ईवीएम की वह व्यवस्था है, जिसमें मतदाता को वोटिंग करने के बाद पता चल जाएगा कि उसका वोट किस दल को गया। वोटिंग के बाद एक पर्ची निकलेगी और वह बताएगी आपका वोट आपके चुने हुए उम्मीदवार के पक्ष में गया है। हलांकि वह पर्ची वोटर अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। लेकिन आयोग के दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन आयोग बार-बार यह कहता रहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई तकनीकी बदलाव नहीं किया जा सकता। आयोग ईवीएम को पूरी तरह सुरक्षित मानता है। आयोग के विचार में ईवीएम चिप आधारित सिस्टम है। इसमें एक बार ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है।

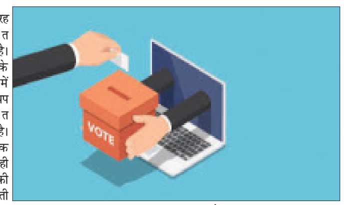

चिप में संग्रहित डाटा का लिंक कहीं से भी जुड़ा नहीं होता है उस स्थिति में इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ और हैकिंग नहीं की जा सकती। यह ऑनलाइन सिस्टम पर भी आधारित नहीं होता है। ईवीएम में वोटिंग क्रमांक सीरियल से सेट होता है। यह पार्टी के अधार के बजाय उम्मीदवारों का नाम वर्णमाला के अधार पर होता है, जिसमें पहले राष्ट्रीय, फिर क्षेत्रिय, दूसरे दल और निर्दलीय होते हैं।हलांकि चुनाव आयोग ने 2009 में ऐसे लोगों को आमंत्रित किया था, जिन्होंने ईवीएम मशीन को हैक करने का दावा किया था। लेकिन बाद में यह साबित नहीं हो सका। अयोग की तरफसे सर्वोच्च न्यायालय में भी हैक का दावा करने वालों को भी चुनौती दी गई थी, लेकिन ऐसा दावा करने वाला कोई भी शख्स मशीन को हैक नहीं कर पाया। वहीं 2010 में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ईवीएम को हैक करने का दावा किया था, जिसमें बताया गया था कि एक मशीन के जरिए मोबाइल से कनेक्ट कर इसमें बदलाव किया जा सकता है।

बिहार में राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सियासी दलों ने कमर कस लिया है। कोरोना संक्रमण काल में गृहमंत्री अमितशाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल चुनावी रैली कर चुके हैं। आरजेडी और दूसरे दल भी चुनावी गणित को फिट करने में जुट गए हैं। लेकिन ईवीएम को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं। फिर सवाल उठता है कि चुनाव आयोग मताधिकार के दूसरे विकल्पों पर विचार क्यों नहीं करता है। देश में ऑनलाइन वोटिंग की मांग भी उठ रही है। यह विकल्प कम खर्चीला भी है। आज के दौर में सबकुछ ऑनलाइन हो गया है फिर ऑनलाइन वोटिंग पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार डिजिटलाइजेशन पर अधिक जो देर रही है उसे आयोग के सामने यह विकल्प रखना चाहिए।

फिलहाल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और उसके दावे पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यह देश की सबसे बड़ी निष्पक्ष और लोकतांत्रिक संस्था है। स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना आयोग का नैतिक दायित्व भी है। यहां किसी की जय पराजय का सवाल नहीं बल्कि बात स्वस्थ्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता का है। ईवीएम पर आयोग सुप्रीमकोर्ट तक पहुँच अपनी स्थिति साफ कर दिया है। लेकिन ऑनलाइन वोटिंग की शुरुवात आयोग को प्रयोग के तौर पर बिहार से करनी चाहिए।

जनाधार विहिन नेता बने कांग्रेस में पदाधिकारी

कांग्रेस पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखने की घटना के बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने सोनिया गांधी को अगले एक साल के लिए फिर से कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के संगठन में कई बदलाव किए हैं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कांग्रेस कार्यसमिति व कांग्रेस के महासचिव के पदों पर किया गया हैं। हालांकि असंतुष्ट गुट के 23 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष से कांग्रेस कार्य समिति के प्रत्यक्ष चुनाव कराने की मांग की थी। लेकिन उनकी इस मांग को नजरअंदाज कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों का नामांकन कर दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस की सबसे शक्तिशाली कांग्रेस कार्य समिति में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ महासचिव मोतीलाल वोरा, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुईस फ्लेरियो व छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को सदस्य से हटा दिया है। उनके स्थान पर तारीक अनवर, पी चिदंबरम, रणदीपसिंह सुरजेवाला व जितेंद्र सिंह को नए सदस्य के तौर पर कांग्रेस कार्यसमिति में शामिल किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद को पार्टी महासचिव पद से हटा दिया गया है। मगर उन्हें कार्यसमिति में बनाए रखा है। इसके अलावा आनंद शर्मा व मुकुल वासनिक को भी फिर से कार्यसमिति में रखा गया है। कांग्रेस संगठन के फेरबदल में गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा, मलिकार्जुन खड़गे, लुईस फ्लेरियो को महासचिव पद से हटा दिया गया है। हालांकि इनमें से गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस कार्यसमिति में बनाए रखा गया है। इसी तरह अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीमती आशा कुमारी, गौरव गोगोई व रामचंद्र खुंटिया को प्रदेश प्रभारी पद से हटाया गया है।

कांग्रेस संगठन में अभी मात्र 9 लोगों को महासचिव बनाया गया है जबकि पहले इनकी संख्या 11 थी। कांग्रेस महासचिवो में बिहार के तारिक अनवर, हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला, राजस्थान के जितेंद्र सिंह, दिल्ली के अजय माकन, महाराष्ट्र के मुकुल वासनिक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, प्रियंका गांधी, केरल के केसी वेणुगोपाल के नाम शामिल है। कांग्रेस में किए गए हाल ही के फेरबदल में सबसे अधिक फायदे में तारीक अनवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, व जितेंद्र सिंह रहे। जिन्हें महासचिव बनाए जाने के कारण कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्यता भी मिल गई। रणदीप सिंह सुरजेवाला तो अहमद पटेल की तरह कांग्रेस की सभी समितियों के सदस्य बनाए गए हैं। चर्चा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल होने के कारण उनकी काट के रूप में हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस संगठन में आगे बढ़ाया जा रहा है।

कांग्रेस संगठन में किए गए फेरबदल में लोकसभा चुनाव जीतने वाले 52 सांसदो में से सोनिया गांधी व राहुल गांधी के अलावा किसी को कहीं भी जगह नहीं दी गई है। सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए गए पदाधिकारियों में अधिकांश राज्यसभा के सदस्य या पूर्व में मंत्री रहे नेता हैं। कांग्रेस कार्यसमिति के अध्यक्ष सहित बाईस सदस्यों में सोनिया गांधी व राहुल गांधी ही लोकसभा सदस्य हैं। 9 लोग राज्यसभा के सदस्य हैं। जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एके एंथोनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, मलिकार्जुन खड़गे व पी चिदंबरम के नाम शामिल है। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य एके एंथोनी, गुलाम नबी आजाद, हरीश रावत, ओमन चांडी पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा गई खंगम उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कार्य समिति में सदस्य बने मलिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत, अंबिका सोनी, अजय माकन, जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर, रणदीप सुरजेवाला, रघुवीर मीणा पिछले चुनाव में पराजित हो चुके हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए 9 महासचिव में एक भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है। तारिक अनवर शरद पवार के साथ सोनिया गांधी का विरोध करते हुए कांग्रेसी छोड़ गए थे। लंबे समय के बाद पिछले वर्ष उनकी कांग्रेस में फिर से वापसी हुई थी। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेसी टिकट पर लड़ा था मगर हार गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा में विधानसभा के लगातार दो बार चुनाव हार चुके हैं। एक बार तो उन्होंने विधायक रहते विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और उसमें बुरी तरह हार गए थे। जितेंद्र सिंह राजस्थान में अलवर से लगातार दो बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। अजय माकन नई दिल्ली सीट से लगातार दो बार लोकसभा चुनाव में करारी हार झेल चुके हैं।

मुकुल वासनिक 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए थे तथा 2019 में उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों ही जगह हार गए थे। ओमान चांडी के केरल में मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस की सरकार ही चली गई थी। प्रियंका गांधी ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी महासचिव बनने के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा की सीटों में खासी कमी हुई है। केसी वेणुगोपाल ने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। केरल में उनकी सीट पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी प्रत्याशी को माकपा के हाथों हारना पड़ा था।

कांग्रेस संगठन में कुछ नए लोगों को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल, राजीव शुक्ला, जितिन प्रसाद, कर्नाटक के दिनेश गुंडू राव, मनीकम टैगोर, राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव, विवेक बंसल, मनीष चौहान, कुलदीप सिंह नागरा के नाम शामिल है। कांग्रेस पार्टी में संगठन चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय चुनाव अथॉरिटी का गठन किया गया है। जिसका अध्यक्ष गांधी परिवार के वफादार मधुसूदन मिस्त्री को बनाया गया है। इसमें राजेश मिश्रा, कृष्णा बायरेगौड़ा, एस ज्योति मनी, अरविंदर सिंह लवली को सदस्य बनाया गया है। इस अभिकरण को बनाते समय कहा गया था कि भविष्य निकट भविष्य में जल्दी ही कांग्रेस संगठन के चुनाव करवाए जाएंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष को मदद व सलाह देने के लिए 6 सदस्यों की एक विशेष कमेटी का भी गठन किया गया है। जिसमें एके एंटोनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक व रणदीप सिंह सुरजेवाला को शामिल किया गया है। यह कमेटी अगले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अधिवेशन तक काम करती रहेगी।

रमेश सर्राफ धमोरा, लेखक

कहने को तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया। जिससे अब कांग्रेस संगठन आने वाले समय में अधिक सक्रिय व मजबूत होकर काम कर सकेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र लिखने वाले 23 से असंतुष्ट नेताओं की मांग को भी पूरा कर दिया है। मगर यहां देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस में किया गया यह बदलाव कांग्रेस को संजीवनी देने में कितना सफल होगा।

संगठन के बदलाव में लोकसभा सदस्यों को बिल्कुल भी तरहीज नहीं दी गई है। वही प्रदेशों में बड़े जनाधार वाले नेताओं को भी संगठन से दूर रखा गया है। कांग्रेस संगठन में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो लगातार चुनाव हार रहे हैं तथा जिनका जनता में जनाधार समाप्त हो गया है। संगठन में पदाधिकारी बनाए गए बहुत से नेताओं को तो चुनाव लड़े ही जमाना बीत गया है। उनमें से बहुत से लोग तो लम्बे समय से राज्यसभा के रास्ते संसद में आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए बेहतर होता यदि जनता पर पकड़ रखने वाले नेताओं को बड़े पदों पर आगे लाया जाता। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य से हटाकर स्थाई आमंत्रित सदस्य बनाया गया है जो उनकी पदावनति है। लोकसभा में सदन के नेता को कार्यसमिति में जगह न देना उनके पद की गरिमा को भी कम करता है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि जनाधार वाले नेताओं को अग्रिम मोर्चे पर तैनात करें। ताकि वह अपनी संगठन क्षमता व जनाधार की बदौलत पार्टी को चुनावी राजनीति में जीत दिला सके।

न्यूज ब्रीफ

पत्रकार पर पिस्टल अड़ाकर धमकाने वाला आरोपी पहुंचा जेल

जिला पत्रकार संघ के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को दिया गया ज्ञापन

माही की गूंज, धार। गत दिनों ग्राम कड़ोदकला में पत्रकार दीपक गिरी को पिस्टल दिखाकर एवं पत्रकार दिनेश रघुवंशी के चार पहिया वाहन के कांच फोड़ने वाले और नगर में उत्पात मचाने वाले आरोपी राधेश्याम के विरुद्ध धार जिला पत्रकार संघ के नेतृत्व में पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि, आरोपी राधेश्याम द्वारा पत्रकारों को डराया-धमकाया जा रहा है जो कि स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। इस दौरान एसपी नें पत्रकारों को आश्वस्त किया कि, 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। इस मामले में पुलिस ने सजगता दिखाते हुए मंगलवार को आरोपी राधेश्याम पाटीदार को गिरफ्तार कर बदनावर के न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी राधेश्याम पाटीदार को जेल भेज दिया गया।

आईटीआई में पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए 30 सितंबर तक तिथि बढ़ी

माही की गूंज, खरगोन। प्रदेश के शासकीय और निजी आईटीआई में रजिस्ट्रेशन तथा च्वाइस फिलिंग के लिए अंतिम तिथि में परिवर्तन किया गया है। आईटीआई के लिए रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग की तिथि 25 सितबर से 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है। पूर्व में इसकी अंतिम तिथि 28 सितंबर तय की गई थी। अब यह भी निर्णय लिया गया है कि निजी आईटीआई के लिए रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग के लिए मध्यप्रदेश ऑनलाईन पोर्टल अब 16 अक्टूबर तक खुला रहेगा, जिससे जो छात्र पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके है वे इस अवधि में रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।

सांसद ने संसद में संसदीय क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की मांग की

माही की गूंज, खरगोन। क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल ने अपने संसदीय क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने को लेकर मंगलवार को संसद में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बात रखते हुए कृषि मंत्री से मांग की। सांसद श्री पटेल ने लोकसभा सत्र के दौरान मुंबई, आगरा नेशनल हाइवे स्थित ग्राम स्त्राटी में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की मांग संसद के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री से की है। सांसद में कहा कि, स्त्राटी में कृषि प्रशिक्षण संस्था परिसर में करीब डेढ़ सौ एकड़ परिसर है, जहां सर्वसुविधायुक्त महाविद्यालय बनाया जा सकता है, यहां महाविद्यालय के निर्माण होने से न केवल खरगोन बल्कि बड़वानी, धार जिले के छात्रों सहित किसानों को भी उन्नत कृषि में लाभ मिलेगा और पीएम नरेंद्र मोदी के कृषि को प्रोत्साहित करने के संकल्प को भी गति मिलेगी। सांसद ने कहा क्षेत्र कृषि प्रधान है, क्षेत्र में कृषि विकास के लिए महाविद्यालय की जरुरत है।

प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही की मौत को बनाया पैसे कमाने का जरिया

जनपद में पदस्थ आपरेटर जामले के साथ मिलकर सचिव, रोजगार सहायक और चौकीदार ने धोखे से हडप ली आवास की राशि

माही की गूंज, पेटलावद। (झाबुआ)

पेटलावद विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के रोज नित नए नए आयाम गड़े जा रहे हैं, काम सार्वजनिक हो या हितग्राही को सीधा लाभ वाली योजना भ्रष्ट कैसे भी कर के पैसा कमाने की जुगाड़ लगा लेते हैं। भष्टो का ईमान और स्तर इतना गिर गया है कि, हितग्राहियों की मौत के बाद भी गिद्ध की तरह उसके परिवार को मिलने वाली राशि को भी डकारने में भी परहेज नही करते हैं।

मामला ग्राम पंचायत बेकल्दा का है जहाँ नंदु पिता थावरिया वसुनिया निवासी बेकल्दा ने अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद को लिखित आवेंदन देकर बताया कि, उसके पिता थावरिया वसुनिया के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि पिता के मर्त हो जाने पर दुसरे के खाते में डालकर हड़पने का गम्भीर आरोप लगाया है। नंदु पिता थावरिया वसुनिया बेकल्दा का होकर मेरे पिता थावरिया पिता हिरा के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में स्वीकृत हुआ था, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त का भुगतान प्रार्थी के पिता हितग्राही थावरिया वसुनिया के खाते में जमा हो गई थी, लेकिन इस दौरान प्रार्थी के पिता आवास हितग्राही थावरिया वसुनिया की मृत्यु हो गई। उक्त मकान का कार्य मेरे द्वारा पुर्ण करावाया गया, मेरे द्वारा ग्राम पंचायत रोजगार सहायक व सरपंच को पिता के खाते का भुगतान परिवार को करने का कहा तो, रोजगार सहायक ने कहा कि, तुम मकान बना लो पुरा पैसा अब तुम्हारे या तुम्हारी माता के खाते में एक साथ जमा हो जायेगा और एक दिन रोजगार सहायक सुधाकर बैरागी, सचिव शैलेन्द्र सिंह राठौर, गांव का चौकीदार अमरसिंह खडिया और जनपद में पदस्थ ऑपरेटर जामले जो कि प्रधानमंत्री आवास का कार्य देखते है, मेरे घर आए और कहा तुम्हारे पिता के सारे दस्तावेत दे दो तो तुम्हारे पिता की मृत्यु पर मिलने वाले दो लाख और मकान का पैसा तुम्हारे खाते में जमा हो जायेगे और इन सभी पर विश्वास कर मेरे पिता का आधारकार्ड, बैंक पासबुक, समग्र आईडी , मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि जरूरी दस्तावेजो मुल प्रति ले गए और कहा कि, तुम्हारी राशि आएगी जब बता देगें और वह राशि आपके खाते में जमा हो जाएगी। कई दिनों तक इनके चक्कर लगाने के बाद भी सचिव, रोजगार सहायक, जामले बाबु और चौकीदार ने न तो कोई भुगतान किया न ही मेरे दस्तावेज वापस दिए और मेरे द्वारा बार-बार पुछे जाने पर जनपद के बाबु जामले ने बताया कि, तुम्हारे पैसे चौकीदार अमरसिंह खडिया के खाते में जमा करवा दिए है उससे ले लेना। जब प्रार्थी अमरसिंह चौकीदार के पास पैसे लेने गया तो पैसे देने से मना कर दिया।

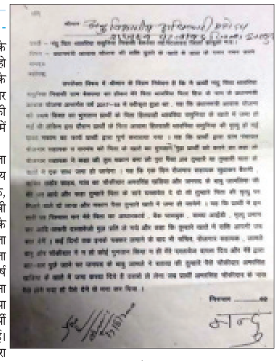

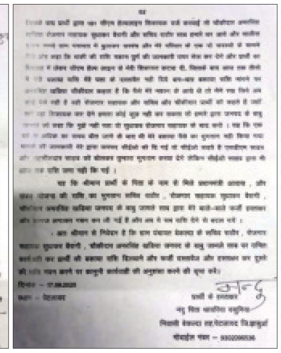

सीएम हेल्पलाइन की शिकायत निपटाने के लिये दिए 40 हजार

हितग्राही के पुत्र नन्दू के द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायक दर्ज करवाई तो, चौकीदार अमरसिंह खडिया रोजगार सहायक सुधाकर बैरागी और सचिव शैलेन्द्र सिंह राठौर शिकायतकर्ता को चालीस हजार रूपए ग्राम पंचायत में बुलाकर सरपंच और मेरे परिवार के एक-दो सदस्यों के सामने दिए और कहा कि, बाकी की राशि मकान पुर्ण की जानकारी उपर भेज कर देगे और मुझे विश्वास में लेकर सीएम हेल्प लाइन से शिकायत कटवा दी, जिसके बाद आज तक चारो के द्वारा बकाया राशि व मेरे पिता के मूल दस्तावेत नहीं दिए बार-बार बकाया राशि मांगने पर अमरसिंह खडिया चौकीदार कहता है कि, पैसे मेरे मकान के आए थे तो मैने रख लिए, अब काई पैसे नही है। वही रोजगार सहायक और सचिव कहते है जहाँ लगे वहा शिकायक अब कर देना हमारा कोई कुछ नही कर सकता, जिसके बाद आवेंदक जनपद के आपरेटर जामले ने कहा कि, सुधाकर रोजगार सहायक से बात करो। मामले को एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी हितग्राही के परिवार को बकाया पैसे का भुगतान नही किया गया। मामले की जानकारी जब आवेंदक द्वारा जनपद सीईओ को दि गई तो सीईओ कहते है, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को बोलकर तुम्हारा भुगतान करवा देगे, लेकिन सीईओ साहब द्वारा भी आज तक राशि जमा नही की गई। आवेदक नन्दू के पिता के नाम से मिले प्रधानमंत्री आवास और संबल योजना की राशि का भुगतान सचिव शैलेन्द्र सिंह राठौर, रोजगार सहायक सुधाकर बैरागी, चौकीदार अमरसिंह खडिया, जनपद के पदस्थ जामले द्वारा फर्जी हस्ताक्षर और कागज लगाकर गबन करने का गम्भीर आरोप लगया है। पूरे मामले की पूर्ण जांच होनी चाहिए आखिर कैसे इन लोगों ने मिलकर फर्जी व्यक्ति को भुगतान करवा दिया और किसके खाते में कितने पैसे जमा हुवे ,अब देखना है कि अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद में मामले में किस प्रकार की जाँच करते हैं और इस प्रकार म्रतक की राशि डकारने वालो पर भी जिम्मेदार कोई कार्यवाही करेगे या हर भ्रष्टाचार की तरह इस भ्रस्टाचार में भी अधिकारी कोई उचित कार्यवाही नही कर भस्टो से मोटा माल कमा कर उनको बचा लेगे।

अवैध उत्खनन कर रहे हैं अज्ञात लोगों के खिलाफ पटवारी ने बनाया पंचनामा

माही की गूंज बमनाला। मुकेश जायसवाल

वेदा नदी के किनारों पर इन दिनों रेत माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन बैखौफ किया जा रहा है, यहां तक कि इन लोगों द्वारा किसानों की जो डीपी लगी है उस के चारों तरफ अवैध उत्खनन किया गया है जिसको लेकर स्थानीय किसानों ने पटवारी को मौके पर ले जाकर वस्तु स्थिति से अवगत करवाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय पटवारी निर्भय सिंह पटेल ने बताया कि, सोमवार को स्थानीय किसानों द्वारा बताया गया की, वेदा नदी के किनारों पर रेत माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है, इस कारण उनके खेतों के लिए जो डीपी लगाई गई उसके चारों और खोद दिया गया जिससे की उनकी पाइपलाइन फूट रही है, इन किसानों की उक्त शिकायत पर पटवारी द्वारा मौके का मुआयना किया गया तो पाया गया कि, अवैध माफिया द्वारा जो उत्खनन किया जा रहा था वे मौके से भाग चुके थे, पटवारी पटेल द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ पंचनामा बनाया एवं वहां से तगारी, फावडे बरामद किए, उक्त जानकारी से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। बमनाला में इन दिनों रसूखदार लोगों द्वारा अवैध उत्खनन जोरों पर किया जा रहा है लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा मोके पर पहूंच कर इनके खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

तहसीलदार देवकुवर सोलंकी का कहना है कि, जो लोग भी अवैध रूप से उत्खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा आवास सहायता योजना

माही की गूंज,झाबुआ।

शैक्षणिक सत्र 2018-19 तथा सत्र 2019-20 की एमपीटीएएसएस में पोर्टल पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा आवास सहायता योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन किया था। परन्तु विद्यार्थियों के बैंक खाते में एनपीसीआई के डीबीटी आधार बेस एक्टिव नहीं होने के कारण योजना राशि खाते में राशि जमा नहीं हो रही है। वे विद्यार्थी स्थानीय शहीद चन्द्रशेखर आजाद, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ के सूचना पटल पर अपना नाम देखकर डीबीटी फॉर्म छात्रवृत्ति प्रभारी प्रो. एमएस चौहान से प्राप्त कर भरकर संबंधित बैंक से आधार लिंक कराएं।

ट्रायसिकल पाकर खिल उठा पूजा सोलंकी का चेहरा

अब उन्हें अधिकारी बनने से नही रोक पायेगी कोई समस्या

माही की गूंज, बड़वानी।

शिक्षा का महत्व क्या है, यह बड़वानी की रहवासी कुमारी पूजा सोलंकी बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसलिये जब उसे 'गरीब कल्याण सप्ताह के तहत अतिथियों ने ट्रायसिकल भेंट की, तब उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, उसने बड़े आत्मविश्वास से बताया कि, अब वह एमपीपीएससी की अपनी इन्दौर की कोचिंग और अच्छी तरह से कर अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त कर लेगी।

ग्राम झोपाली की एमए पास कुमारी पूजा सोलंकी को जैसे ही सामाजिक न्याय मंत्री प्रेमसिंह पटेल के प्रतिनिधि बलवन्तसिंह पटेल ने ट्रायसिकल वितरित की, वैसे ही पूजा के चेहरे की रंगत खुशी के कारण बदल गई। उसने बड़े आत्मविश्वास से बताया कि, वह पोलीटीकल साइंस से एमए पास है और एमपीपीएससी की तैयारी इन्दौर में रहकर कोचिंग के माध्यम से कर रही है।

अपने रूम से कोचिंग सेंटर तक आने-जाने में उसे अत्यधिक परेशानियों का सामना करते हुए अपने साथियों के उपर निर्भर रहना पड़ता है, अगर एक भी साथी किसी दिन कोचिंग नही जाता तो वह भी चाहकर कोचिंग नही जा पाती, किन्तु अब ट्रायसिकल मिल जाने के कारण उसकी यह समस्या दूर हो जायेगी, जिसके कारण वो और अच्छी तरह से अपनी कोचिंग कर बचपन से देखा हुआ अधिकारी बनने का सपना पूरा कर पाएगी।

ग्राम पंचायत ने सूचना अधिकार अधिनियम का उड़ाया माखौल, 16 रूपए प्रति पेज के हिसाब से कर ली वसूली

जानकारी मांगने वाले से 890 पेज के वसूल लिये 14,375 रुपये ओर पकड़ा दी आधी अधूरी जानकारी

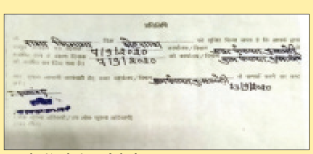

- आरटीआई में मांगी गई जानकारी की रसीद

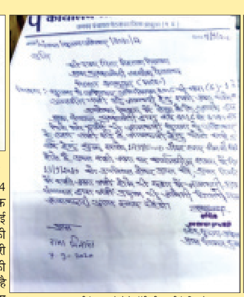

ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी के एवज में फोटो कॉपी की वसुली के लिए भेजा गया पत्र

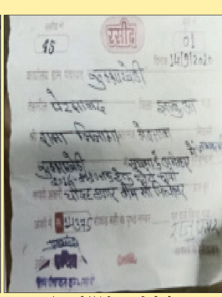

- ग्राम पंचायत में जानकारी लेने के लिए जमा राशि की रसीद

माही की गूंज, पेटलावद। (झाबुआ)

पेटलावद विकास की कुम्भाखेड़ी में बड़ा ही रोचक मामला सामने आया है जहाँ ग्राम पंचायत सचिव ने जानकारी के बदले आफदी रिकॉर्ड अवैध वसूली कर जानकारी मांगने वाले को अधूरी जानकारी उपलब्ध करा दी , सूचना के अधिकार अधिनियम के मामले में पूरे जिले में सम्भवतह ऐसा पहला मामला हो जहा पंचायत से मांगी दी गई जानकारी के लिए प्रति पेज 16 रुपये की वसूली ग्राम पंचायत द्वारा की गई । ग्राम पंचायत के कुभाखेड़ी के रामा निनामा द्वारा आरिटीआई के तहत दिनांक 07.09.2020 को आवेंदन पेश कर ग्राम पंचायत के कार्यो की जानकारी मांगी गई जिस सचिव द्वारा मात्र 04 दिवस के भीतर दिनांक 13.09.2020 चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाने की रसीद दी गई , चुकी जानकारी 05 वर्ष के लम्बे कार्यकाल की थी कागज की संख्या भी तय है ज्यादा ही होने थी लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना किसी जानकारी के कागजो की संख्या देखे आवेंदन दिनांक 07.09.2020 को एक पत्र जारी कर चाही गई जानकारी के लिए 14,375 रुपये जमा करवाने का कहा गया जिसकी सूचना पर आवेंदनकर्ता रामा निनामा में ग्राम पंचायत द्वारा मांगी गई राशि एक मुस्त दिनांक 14.09.2020 को जमा करवा दी गई जिसकी रसीद भी ग्राम पंचायत द्वारा आवेंदनकर्ता को दी गई ओर इसी दिनांक को ग्राम पंचायत द्वारा रामा निनामा को बुलाकर मांगी गई जानकारी दी गई जिसे पंचायत में मौजूद पांच लोगों के बीच मे जानकारी देते हुवे सचिव द्वारा न तो आवेंदनकर्ता को जानकारी देखने दी गई और न ही उपलब्ध कराई गई जानकारी के दिये गए कागजो की संख्या बताई गई न गिनने दिया गया और कहा गया जो भी करना है घर जा कर करो । रामा निनामा द्वारा जब घर पहुँच कर दी गई जानकारी की जाँच की गई तो बता चला कि पंचायत द्वारा न तो पूर्ण जानकारी दी गई न ही ली गई राशि के अनुसार उतने पेज दिए गए रामा निनामा ने बताया कि जब जानकारी के पेज गिने तो कुल 890 पेज ही थे जो कि मुझे 16.16 पैसे प्रति पेज पड़ा और जानकारी के नाम पर पूरी तरह से गुमराह कर आधी अधूरी जानकारी दी गई और कई कार्यो की जानकारी तक नही दी गई ।

जनपद में करी प्रथम अपील

आवेंदनकर्ता रामा निनामा द्वारा जानकारी पूर्ण नही मिलने मुख्य कार्यपालन अधिकारी पेटलावद को अपील कर जानकारी मांगी हैं , रामा निनामा का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा सूचना अधिकार की जानकारी देने के नाम पर की गई अवैध वसूली के लिए जिला कलेक्टर को आवेंदन देकर कार्यवाही की मांग करूंगा , ग्राम पंचायत में फैले भारी भ्रस्टाचार को उजागर करने के लिए जानकारी मांगी है जो पंचायत देने से कतरा रही है।

आंगनवाड़ी भवन नही होने से सहायिका के घर पर लग रहा आगनवाड़ी केन्द्र

निर्माणाधीन भवन एक्सप्रेस वे में हो गया जमीदोज

माही की गूंज, भामल। (झाबुआ)

ग्राम पंचायत भामल के अंतर्गत रूपापाडा फलिए में आंगनवाड़ी भवन नहीं होने से बच्चों को परेशानी हो रही है, पूर्व में जो आंगनवाड़ी भवन था वह निर्माणाधीन 8 वे एक्सप्रेस लेन में ठेकेदार द्वारा जमीदोज कर दिया गया, जिससे सरकारी भवन नहीं होने से बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा हैं कि, निर्माणाधीन 8 लेन एक्सप्रेस में आंगनवाड़ी भवन साथ ही पँचायत द्वारा बनाया गया श्मशान घाट भी ठेकेदार द्वारा जमीदोज किया गया, लेकिन अभी तक नए भवन व नए श्मशान घाट के कार्य की शुरुआत ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई। ठेकेदार का कहना है कि, हमने ग्राम पंचायत में दोनो आगनवाड़ी भवन व श्मशान घाट की राशि डाल दी लेकिन उसका निर्माण अभी तक क्यों नहीं किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। आंगनवाड़ी भवन आज भी सहायिका के घर पर संचालित किया जा रहा है, जिससे खुले में बच्चे बैठने को मजबूर है, साथ ही शासन की योजनाओ का लाभ भी बच्चो को नही मिल पा रहा है।

पूर्व मंत्री ने खराब हुई फसलों का किया अवलोकन

माही की गूंज, खरगोन। पूर्व मंत्री एवं महेश्वर विधायक डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने बारिश से प्रभावित हुई फसलों का अवलोकन किया। उन्होंने महेश्वर के विभिन्न गांवों में जाकर किसानों से मुलाकात कर बारिश से खराब हुई फसलों की जानकारी भी ली। इस अवसर पर कृषि एवं उद्यानिकी विभाग का अमला उपस्थित रहा। डॉ. साधौ आज भी क्षेत्र में फसलों का अवलोकन करेंगी। डॉ. साधौ प्रातः साढे 10 बजे ग्राम धरगांव, प्रातः 11 बजे ग्राम नांद्रा, प्रातः साढे 11 बजे ग्राम कतरगांव, दोपहर 12 बजे ग्राम कोगावां, दोपहर साढे 12 बजे ग्राम पिपल्या, दोपहर 1 बजे ग्राम कोडल्याखेड़ी, दोपहर 2 बजे करही, दोपहर ढाई बजे ग्राम वणी, दोपहर 3 बजे ग्राम बबलाई, दोपहर साढे 3 बजे पाडल्या में बारिश से प्रभावित हुई फसलों का अवलोकन करेंगी। इसके पश्चात शाम 4 बजे महेश्वर के जनपद पंचायत भवन में समीक्षा बैठक करेंगी।

शौचालय बनाने के लिए तोड़ा यात्री प्रतीक्षालय पर दूसरी जगह कर दिया निर्माण शुरू

क्या प्रतिक्षालय की जमीन पर अब होगा अतिक्रमण?

माही की गूंज, पेटलावद।

ग्राम पंचायतों में शुरू हुए तीन लाख तीस हजार की लागत के सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है, कई पंचायतो में इसके निर्माण को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत में होने वाले शौचालय निर्माण के लिए किसी प्रकार की खानापूर्ति नही की गई और बिना शासकीय भूमि चयनित किए मनमाने ढंग से निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए, एसी जगह आपत्ति के बाद निर्माण रोकना पड़ा तो कही पर निर्माण का स्थान भी परिवर्तित करना पड़ा, कई पंचायतो में ग्राम प्रधान ओर सचिव ने बिना अनुमति पुराने शासकीय निर्माण शौचालय के नाम पर तोड़ कर उक्त भूमि को अतिक्रमण करने या कराने की नीयत से खाली करवा दी और दूसरे स्थान पर शौचालय निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ग्राम पंचायत बनी में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहाँ बनी-राजगढ़ मुख्य मार्ग पर बस स्टेशन पर बने पुराने यात्री प्रतिक्षालय को तोड़ दिया और जब गाँव के लोगो ने ग्राम पंचायत से पूछा तो कहा गया यहाँ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है लेकिन प्रतिक्षालय तोड़ने के बाद पंचायत ने शौचालय का निर्माण उस स्थान से लगभग तीन सौ मीटर दूर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिससे ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्राम बनी में पहले से मुख्य मार्ग से लगी लोकनिर्माण विभाग की बेश कीमती भूमि पर लोगो नें अवैध अतिक्रमण कर लिया जो कि निकट भविष्य में बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है, ऐसे में रोड किनारे बने प्रतिक्षालय को बैठने लायक बनाने क जगह उसे तोड़ कर खाली हुई भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने या फिर किसी अतिक्रमणकर्ता की नजर में आई इस भूमि को योजनाबद्ध तरीके से रिक्त किया गया है जिसे बाद में किसी न किसी तरीके से बेचा जा सके, टूटे प्रतिक्षालय के एक हिस्सा पहले से कब्जा किया जा चुका है ऐसे में खाली हुई भूमि कितने दिन अतिक्रमण मुक्त रहेगी इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ग्रामीणों सहित ग्राम बनी के जनप्रतिनिधि इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद को आवेंदन देने की बात कर रहे हैं, वही बनी पंचायत के सचिव जामसिंह का कहना है कि, यात्री प्रतिक्षालय अत्यंत जर्जर हो गया था यहाँ नया प्रतिक्षालय बनाया जाएगा।

टूटे हुए प्रतिक्षालय ओर नवीन शौचालय निर्माणाधिन

जमुनिया के लोग चार साल बाद भी रोड को तरसे कच्चे और कीचड़ भरे मार्ग से गुजरने को मजबूर

कचराखदान पंचायत में फिर आया बिना रोड बनाए पैसे निकालने का मामला

माही की गूंज पेटलावद। राकेश गेहलोत

कब और कैसे जागेगा प्रशासन ये तो नही पता लेकिन गूंज की पहल जरूर रंग ला रही हैं और आमजन अब जागरूक हो रहे हैं, शासन द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यो की जानकारी देने वाले पोर्टल पर ग्राम पंचायत द्वारा सरकार को भ्रमित कर चढ़ाई गई गलत जानकारी को देख कर उसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दे गूंज लगातार ऐसे कार्यो का खुलासा मय प्रमाण के कर रही है, जो सरकार को बताए गए हैं कि, कार्य कर दिए गए हैं लेकिन धरातल पर कुछ नही है, बिचारे सीधे-सादे ग्रामीण शासन का पैसा डकारने वालो पर कार्रवाई नही बल्कि गाव के विकास के लिए आए पैसे जो कि फर्जीवाड़े में सरपंच-सचिव और अधिकारियों में बंदरबाट हो गए हैं उसे उनकी जेब से निकलवा कर अधुरे पड़े कार्यो को पूरा करने की मांग कर रहे, ताकि उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके लेकिन जो मामले अपराध की श्रेणी में आता है उन पर जिम्मेदार कार्यवाही करना तो ठीक उन कार्यो को पूरा करवाने तक मे रुचि नही दिखाते, केवल जाँच, प्रतिवेदन और पंचायती धाराओं के नाम पर गुमराह कर समय निकाल कर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है जिसके एक नही विकास खण्ड में कई उदाहरण मौजूद हैं।

जमुनिया में नही बना रोड, जो बने वो भी घटिया

ग्राम पंचायत कचराखदान के अंतर्गत पूर्व में दो रोड ऐसे अलग-अलग गाव में सामने आ चुके हैं जो वर्ष 2017 में स्वीकृत तो हुए लेकिन बने नही और उसकी राशि

पंचायत द्वारा आहरण कर ली गई है। ग्राम पंचायत कचराखदान के गलिया डोडियार ने जब पंचायत दर्पण को

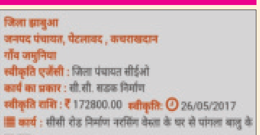

जिला झाबुआ
जनपद पंचायत, पेटलावद , कचराखदान
गाँव जमुनिया
स्वीकृति एजेंसी : जिला पंचायत सीईओ
कार्य का प्रकार : सी.सी. सड़क निर्माण
स्वीकृति राशि : ₹ 172800.00 स्वीकृति: 26/05/2017
कार्य : सीसी रोड़ निर्माण नरसिंग वेस्ता के घर से पांगला बाबु के घर तक

देखा तो पता लगा कि, पंचायत के ग्राम जमुनिया में नरसिंह वेस्ता के घर से पांगला बाबू के घर एक लाख 72 हजार आठ सौ का सीसी रोड 26 मई 2017 को स्वीकृत हुआ था, आज तक रोड तो नही बना लेकिन रोड के लिए वर्ष 2017 में जारी राशि की बंदरबाट हो चुकी हैं और ग्रामीण आज भी रोड को तरस रहे है कीचड़ और पथरीले मार्ग से ही गुजरने पर मजबूर हैं। जमुनिया गाँव मे बने दूसरे दो रोड की वर्तमान स्थिति को भी देखा जाए तो बिना मापदंड और घटिया निर्माण की गवाही धरातल पर बना रोड खुद गवाही देगा लेकिन जो अधिकारी बिना बने रोड जिनकी राशि तक निकाल ली गई उस पर कोई कार्यवाही को तैयार नही है तो फिर आधे-अधूरे व घटिया निर्माण पर कब कार्यवाही करेगे? ये भी बड़ा प्रश्न है।

ग्रामीण गलिया डोडियार ने कहा कि, ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत जल्द ही प्रमाण सहित जिला कलेक्टर को करूंगा।

गुरूजियों की 12 वर्ष की क्रमोन्नित प्रदाय की जाए

- राज्य सहायक अध्यापक संघ ने की सहायक आयुक्त से भेंट

माही की गूंज, झाबुआ। राज्य सहायक अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मंगलवार को दोपहर कलेक्टोरेट पहुंचकर आदिवासी विकास विभाग झाबुआ के सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य से मुलाकात कर उन्हे एक पत्र प्रेषित किया। जिसमें वर्ष 2008 में पात्रता परीक्षा पास गुरूजियों (प्राथमिक षिक्षकों) के 12 वर्ष की क्रमोन्नित संबंधी मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल में शामिल संघ के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश पालिवाल, जिला संगठन मंत्री उदयसिंह बिलवाल, रमणलाल नायक तथा रणछोड़ राठौर आदि द्वारा सहायक आयुक्त आर्य से मिलकर उन्हें एक पत्र देकर अवगत करवाया कि वर्ष 2008 में जो गुरूजी पात्रता परीक्षा पास कर चुके है, उनके 17 अप्रेल 2020 को 12 वर्ष पूर्ण हो चुके है। उन्हें शासन के नियमानुसार क्रमोन्नित का लाभ मिलना चाहिए। जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। जिस पर एसी आर्य ने तत्काल कार्रवाई हेतु संघ के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया

माही की गूंज, झाबुआ। ग्राम कालीदेवी में मंगलवार को आदिमजाति सहकारी मर्यादित संस्था पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का भोपाल से सीधा प्रसारण टीवी पर कृषकों को दिखाया गया। सबको साथ सबका विकास योजना अंतर्गत अब पशु पालकों को भी 0 प्रतिशत पर ऋण दिया जाएगा तथा मत्स्य पालकों को भी 0 प्रतिशत पर ऋण दिया जाएगा। आदिम जाति सहकारी संस्था पर नए सदस्य बनाए गए, जिन्हें क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए। जिससे उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बापुसिंह भूरिया, मदन भूरा, लालसिंह गामड़, मूनसिंह कटारा, करण अमिलिया, कुंवरसिंह भूरिया आदि उपस्थित थे।

महिला सशक्तिकरण तथा जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

- कानूनी जागरूकता ही महिला सशक्तिकरण का आधार

माही की गूंज, झाबुआ। मंगलवार को ग्राम बिलीडोज में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा महिला सशक्तिकरण तथा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुदूर ग्रामीण पिछड़ें क्षेत्रों की जमीन से जुड़ी हुई 60 महिलाओं को शिविर में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। सबसे पहले प्रवेश द्वार पर सभी की टर्मल स्केनिंग कराई गई सभी भाग लेने वाली महिलाओं को प्लास्टिक फोल्डर के साथ-साथ लिखने के लिए राईटिंग पैड- पेन तथा पर्सनल यूज हेतु प्रत्येक महिला को छोटा सेनेटाईजर तथा मास्क दिया गया।

कोरोना संक्रमण वायरस को देखते हुए लगभग 6 से 7 फुट की दूरी पर पृथक-पृथक बैठाया गया था। सभी महिलाओं ने मास्क पहना हुआ था। महिलाओं को कानूनी जागरूकता के लिए संवैधानिक तथा विभिन्न उपयोगी कानूनों की विस्तार से जानकारी दी गई तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जैसे- लाडली लक्ष्मी, स्किल इंडिया, वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को मिलने वाली काउंसलिंग एवं सुविधाओं के बारे में महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी मीरा गाडगे ने जानकारी दी। शिविर को अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश देवलिया, जिला जज तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश गुप्ता, अधिवक्ता प्रतिभा सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजली सिंह आदि ने संबोधित किया। शिविर में महिला बाल विकास द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत 05 बालिकाओं इन्द्रा मंडोड, अलका मंडोड, प्रियंका मड़ोड, राधिका मंडोड तथा अर्पिता डामोर को प्रति बालिका को 1 लाख 18 हजार रूपए की सहायता राशि का प्रमाण-पत्र देकर जिला न्यायाधीश तथा अन्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। विशेष रूप से कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकुमार चौहान, जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल, शालिनी व्यास तथा जिम्मी उपस्थित रहें। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका शुभा गुप्ता के ने किया।

कोरोना महामारी एवं सामान्य रूप से दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देगा सामाजिक महासंघ

माही की गूंज, झाबुआ।

वर्ष 2020 में मार्च माह से संपूर्ण विश्व सहित भारत देश में कोरोना महामारी ने जबरदस्त तांडव मचाया है। जिससे मप्र का झाबुआ जिला भी अछूता नहीं है। जिले में कई लोग कोरोना महामारी से पीड़ित होकर असमय काल के गाल में समाहित हो चुके हैं। साथ ही झाबुआ शहर में इनको मिलाकर लगभग 40 लोग ऐसे भी है, जो सामान्य बिमारियों से भी दिवंगत हुए हैं।

इन सभी को सामाजिक महासंघ झाबुआ की ओर से 24 सितंबर, गुरूवार देर शाम 7.30 बजे से स्थानीय पैलेस गार्डन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर भावांजलि दी जाएगी। यह आयोजन कोविड-19 के नियमों के पालन करते हुए आयोजित होगा। जिसमें झाबुआ के विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रमुख पदाधिकारी एकत्रित होकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मोमबत्ती जलाकर दिवंगत हुई इन आत्माओं को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही 2 मिनट का मोन भी रखा जाएगा। जिसमें दिवंगत आत्माओं की आत्मा शांति के लिए परम् पिता परमात्मा से प्रार्थना की जाएगी।

झाबुआ सहित जिले के 60 दिवगंतों को दी जाएगी एकसाथ श्रद्धांजलि

सामाजिक महासंघ के नीरजसिंह राठौर, डॉ. केके त्रिवेदी एवं यशवंत भंडारी ने बताया कि दिवंगत हुए लोगों के परिजन भी अनुकूलता अनुसार श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।। केवल 15 मिनिट के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मॉस्क, सैनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान सामाजिक संगठनों द्वारा रखा जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बकायदा झाबुआ के दिवंगत श्रेष्ठजनों का होर्डिंग भी बनाया जा रहा है। जिसमें कोरोना महामारी से दिवंगत हुए महानुभावों के अलावा सामान्य रूप से दिवंगत हुए लोगों के फोटो भी लगाए जा रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से जिले एवं झाबुआ शहर के करीब 60 लोगों को एकसाथ श्रद्धांजलि दी जा रही है।

जीके शर्मा अंर्तराष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राम्हण महासभा के जिलाध्यक्ष मनोनीत

माही की गूंज, झाबुआ। अंर्तराष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राम्हण महासभा के अध्यक्ष एवं महासचिव की अनुसंषा पर अंर्तराष्ट्रीय संगठन प्रभारी एसएन गौतम ने झाबुआ के गोपाल कॉलोनी निवासी गोपालकृष्ण शर्मा को महासभा का झाबुआ जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। श्री शर्मा वर्तमान में जिले की कई संस्थाओं से जुड़े हुए है।

शर्मा की महासभा में जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर उनसे आषा व्यक्त की गई कि वे समाजहित में कार्य करते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वे वर्तमान में भारतीय मजदूर संघ के झाबुआ-आलीराजपुर जिले के संयोजक के साथ वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के संभागीय अध्यक्ष तथा पेंषनर महासंघ के जिलाध्यक्ष पद पर रहते हुए कार्य कर रहे है। वे सेवानिवृत्त कर्मचारी होकर सामाजिक कार्यों में हमेषा अग्रणी रहते है। उनके मनोनयन पर ब्राम्हण समाजजनों सहित उक्त समस्त संस्थाओं के पदाधिकारी-सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की है।

तप चक्रेश्वरी द्वारा 91 उपवास के प्रत्याख्यान

माही की गूंज, थांदला। वर्षावास हेतु विराजित प्रवर्तक जिनेन्द्रमुनिजी मसा आदि ठाणा तथा साध्वी निखिलशीलाजी मसा आदि ठाणा के दर्शनार्थ मेघनगर से तप चक्रेश्वरी बहन स्नेहलतादेवी वागरेचा 87 उपवास की उग्र तपस्या में पहुंच कर पूज्यश्री से 91 उपवास की तपस्या के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। प्रवर्तक श्री ने छंद व मांगलिक सुनाकर तप की मंगलकामना व्यक्त की। इस अवसर मेघनगर के अन्य तपस्वी सुमित ब्रजवानी ने 41 उपवास, शशिबेन नांदेचा ने 21 उपवास, चांदमल चोरड़िया ने 16 उपवास तथा कश्मीरी बेन बलकवाड़ा ने 13 उपवास की तपस्या के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। जैन लघु सर्वतो भद्र रानी तप कर रही थांदला की बेटी तपस्वी सपना वागरेचा ने भी पूज्यश्री से प्रत्याख्यान लिए। जिसके बाद तप चक्रेश्वरी बहन साध्वी मण्डल के दर्शनार्थ महिला स्थानक पहुंची। वहा संघ की ओर से अध्यक्ष जितेंद्र घोड़ावत ने शाब्दिक बहुमान किया तथा धर्म सहायक व मेघनगर श्रीसंघ के पूर्व अध्यक्ष हंसमुखलाल वागरेचा व तपस्वी बहन सपना वागरेचा का शाल माला से बहुमान पूर्व सचिव रजनीकांत शाहजी, पूर्व उपाध्यक्ष मोहनलाल लोढ़ा, माणकलाल लोढ़ा, नवयुवक मंडल के पूर्व अध्यक्ष हितेश शाहजी व रवि लोढ़ा द्वारा किया गया।

ट्रासफार्मर का काम कर रहे लाइन मैन की करंट लगने से हुई मौत

माही की गूंज, रतलाम। रतलाम जिले के गांव मावता में सोमवार शाम 4 बजे ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे लाइनमैन कैलाश पिता वरदीचंद माली (38) निवासी पंचेवा की करंट लगने से मौत हो गई, शव को पीएम कराने के बाद परिजनों को सौपा कर मामले की जांच कालूखेड़ा पुलिस कर रही है। कालूखेड़ा ग्रिड के सुपरवाइजर ने बताया कि, बिना परमिट के काम कर रहे थे ट्रांसफार्मर में रिटर्न करंट आने से करंट लगने की संभावना लग रही है।

दिव्यांग बालकों को मनमाफिक स्कूल प्रवेश की सवैधानिक सुविधा, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का समय रहते उपचार संभव बोले विषेषज्ञ

चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 12 वी ई संगोष्ठी में हुई संपन्न

माही की गूंज, झाबुआ

एक बच्चे के लिए मोबाइल पर चालीस मिनिट से अधिक समय बिताना उसके मानसिक विकास को अवरुद्ध करता है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि, बच्चा रुचिकर पारस्परिक संवाद में चालीस मिनिट से अधिक समय स्क्रीन पर बिताता है या केवल अपनी काल्पनिक दुनिया मे एकपक्षीय आंनद लेता है। क्वालिटी स्क्रीन टाइम 40 मिनिट से अधिक नुकसानदेह नही है, बशर्ते सीखने और रुचिकर संवाद की स्थिति हो। कोरोना काल मे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस से निर्मित सामयिक परिस्थितियों पर रविवार को चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 12वी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ख्यातनाम बाल विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. जफर मिनाई (यूके) ने यह बात कही। संगोष्ठी को सामाजिक न्याय विभाग के सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के मेम्बर प्रकाश मारू ने भी संबोधित किया।

डॉ. जफर मिनाई ने बताया कि, बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध होना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसे हम तत्काल पहचान कर उचित उपचार के माध्यम से परिमार्जित कर सकते है। बालकों का मानसिक विकास न होना एक सामाजिक त्रासदी भी है क्योंकि ऐसे बालक अन्ततः समाज मे अपना समुचित योगदान देने से वंचित हो जाते है। उन्होंने बताया कि, बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप विकसित होने जा रहा है या नही इसकी पहचान परिवारजन घर में ही सामान्य बाल सुलभ लक्षणों से कर सकते है। मसलन दो माह में अगर बच्चा मुस्कराता है, चार माह में गर्दन संभालने लगता है, आठ माह में सीधी पीठ से बैठता है और एक साल में पैर के बल खड़ा होने लगता है तो उसके स्वाभाविक विकास में कोई खास अवरोधक नही आते है। अगर ऐसा नही है तो हमें तत्काल न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर की संभावनाओ पर ध्यान देकर उपचार सुनिश्चित करना चाहिए। डॉ. मिनाई ने बताया कि, भारत मे कुछ लोग इन संकेतों की यह कहकर अवहेलना करते है कि, हमारे परिवारों में बच्चे देर से बोलना या खड़े होना शुरू करते है। यह स्थिति अक्सर बहुविकलांगता को जन्म देती है। उन्होने बताया, अगर जन्म के समय बच्चे का वजन दो किलो से कम है या वह प्रसव उपरांत रोता नही है अथवा उसके पीलिया के लक्षण निरन्तर है, तब हमें उच्च प्राथमिकता पर ऐसे बच्चों को हाईरिस्क कैटेगरी में रखना चाहिए। डॉ. मिनानी ने ब्रेन टॉनिक को एक छलावा बताते हुए ऐसे उत्पादों से दूर रहने की सलाह दी। क्युकी ब्रैंन टॉनिक केन्द्रिय तंत्रिका तन्त्र को प्रभावित कर असन्तुलन भी उतपन्न कर सकता हैं। ड़ॉ. मीनाई ने बताया, ऑटिज्म व कयी डिसआर्डर को काफी हद तक माता-पिता के सहयोग से ठिक कीया जा सकता हैं।

88 हजार बच्चो का स्वास्थ्य बिमा करवाया

सामाजिक न्याय विभाग के केंद्रीय सलाहकार मंडल के सदस्य पंकज मारू ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि, मप्र में हर्ष फाउंडेशन के सहयोग से निरामय योजना के तहत 88 हजार जरूरतमंद और सरंक्षण श्रेणी के बच्चों को स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है। नवीन दिव्यांगता कानून में सरकार ने 21 तरह की दिव्यांगता को कवर किया है। इस कानून की खासियत यह भी है कि, दिव्यांग बच्चों को उनके मनमाफिक स्कूल में प्रवेश की गारंटी दी गई जबकि शिक्षा अधिकार कानून केवल समीपवर्ती स्कूल में प्रवेश की पात्रता देता है। साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी यह कानून लागू है जिसके चलते दिव्यांग बालक इनमें प्रवेश ले सकते है। श्री मारू ने बताया कि, दिव्यांग बालकों के लिए संचालित राज्य एवं केंद्र सरकार के सयुंक्त सरकारी स्कूलों को अब शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता से चलाने पर भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सहमत है। सभी जिला मुख्यालय पर डीडीआरसी के माध्यम से दिव्यांग बालकों के पुनर्वास एवं अन्य सहायता की व्यवस्था की गई है। मौजूदा सरकार ने क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्रों की संख्या 8 से बढाकर 20 कर दी है। इसके अलावा नेशनल फंड स्कीम के जरिए प्रतिभाशाली दिव्यांग बालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश पढ़ने के लिए ऐसे बालकों को 20 लाख तक की सीधी सुविधा की पात्रता है। गंभीर बीमार बच्चों को एक लाख की मदद भी उपलब्ध है। श्री मारू ने बताया कि, पर्सन, फेमिली, प्रोफेशन और पॉलिसी के स्तर पर दिव्यांगता को समेकित करके ही इस जंग को जीता जा सकता है। नए दिव्यांग कानून में इसी समेकन का प्रयास किया गया है।

इस सेमिनार में मप्र के अलावा बिहार, ओडीसा, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आसाम, उत्तराखंड, चंडीगढ़, यूपी, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब के बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि, सभ्य समाज मे दिव्यांगता से पीड़ित बालकों और उनके परिजनों के प्रति हमें सहानुभूति प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने दोनों अतिथि वक्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। सेमिनार का संयोजन करते हुए फाउंडेशन के सचिव डॉ. कृपाशंकर चौबे ने बताया कि, सीसीएफ बाल सरंक्षण और विकास के क्षेत्र में एक बहुउपयोगी केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को आकार देने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत अखिल भारतीय स्तर पर विशेषज्ञों का स्वतंत्र पूल बनाया जा रहा है, सीसीएफमीडिया प्रभारी डॉ अजय खमेरिया व सीडब्लूसी अध्यक्ष निवेदिता सक्सेना ने उक्त जानकारी दी।

चहेल्लुम की तैयारी, हुसैन टेकरी में बाहरी लोग ना जुटें

होटल-लॉज में पहले से ठहरे लोगों के नाम-पते किए जायेगे नोट

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के जावरा में हुसैन टेकरी शरीफनवाज पर 28 सितंबर से शुरू हो रहे 10 दिनी चेहल्लुम की व्यवस्था जुटाना पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती है। वैसे तो प्रशासन ने खंदक और जुलूस समेत चेहल्लुम के सारे बड़े व सार्वजनिक आयोजन निरस्त कर दिए हैं। सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी में हुसैनी मिशन को इमामबाड़ा परिसर में सांकेतिक आयोजन की अनुमति दी हैं लेकिन संक्रमण की रफ्तार यही रही तो संभव है, इसमें भी प्रशासन हस्तक्षेप करे। हर साल पुलिस बल लगता है ताकि बाहर से आने वाले जायरीनों को असुविधा नहीं हो। इस बार अभी से अतिरिक्त पुलिस बल इसलिए लगाया है ताकि बाहरी लोग यहां ना आएं, ये प्रतिबंध भी सुरक्षा के लिहाज से ही है क्योंकि मौजूदा स्थिति में कोरोना सबके लिए बड़ा खतरा है, इसलिए पुलिस की तैनाती कर लोगों को यहां आने से रोका जा रहा है। यहा प्रयाप्त पुलिस बल तैनात है, जिसमें ये वे पुलिसकर्मी हैं जो पहले यहां चेहल्लुम में ड्यूटी दे चुके हैं। शनिवार से पुलिस ने टेकरी परिसर में स्थित होटल, लॉज की चेकिंग की। यहां पहले से जो लोग ठहरे हैं उनकी जानकारी रजिस्टर में दर्ज की और यह पता लगाया कि, कौन-कब से आया हुआ है और उनकी वापसी कब होगी। वहीं लॉज व होटल संचालकों को स्पष्ट कह दिया है कि, वे बाहरी नए लोगों को ठहरने की अनुमति नहीं दें। आईए थाना प्रभारी जनकसिंह रावत ने बताया आसपास जो गांव है, वहां कई बार चेहल्लुम के दौरान लोग अपने मेहमानों को बुला लेते हैं। उन्हें भी समझाइश दे रहे हैं कि, चेहल्लुम अवधि में मेहमान नहीं बुलाएं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, सिर्फबाहरी ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी अनावश्यक जुटने नहीं देंगे ताकि भीड़ ना लगे।

अपने काले धंधों का साम्राज्य बढ़ाने हेतु प्रभाव स्थापित करने के लिए करते है धार्मिक व सामाजिक आयोजन

सर्कस मास्टर भी अपने खाद्यान्न की काला बाजारी के साम्राज्य को बढाने के लिए धार्मिक आयोजन कर बन गया समाजसेवी

माही की गूंज, झाबुआ।

कम समय में अपने काले कारनामों के साथ काला बाजारी कर व अपना माफियाई राज स्थापित कर बड़े पैमाने पर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए माफिया एवं कालाबाजारी करने वाले कूटनीतिज्ञ के साथ धार्मिक आयोजन व समाज-सेवी बन अपने प्रभाव को स्थापित करने में कोई कसर माफिया नहीं छोड़ते हैं और आम लोग भी कहीं न कहीं ऐसे काले कारनामे करने वाले कूटनीतिज्ञो द्वारा अपने प्रभाव के साथ चका-चौध बताने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ जाते है, नतीजन उनके काले कारनामों के आगे आने में यह सोच कर संकोच करते हैं कि, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है और अगर उनके काले कारनामे के आगे आएंगे तो उनका कुछ नहीं होगा, परंतु अधिकारी उल्टा ऐसे कूटनीतिज्ञ कालाबाजारी करने वाले व माफ्यिाओं को प्रभावशील बनाकर आमजन को ही मुंह की खानी पड़ेगी और इसी माफियाई प्रभाव के साथ आम लोग इनके काले कारनामो के सामने आने की हिमाकत नहीं दिखाते है।

इसी प्रभाव को बनाने के लिए माफिया उर्फ कालाबाजारी करने वाले अपने साम्राज्य को बढ़ाने हेतु धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को बड़ा रूप देकर अपने-आपको समाजसेवी बनाकर राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित कर व अपने काले साम्राज्य को बढ़ाते हैं और अपने काले साम्राज्य के साथ आतंक का पर्याय बन जाते हैं और अपने आतंक के किसी सिलसिले में राजनितिक सरक्षण के साथ वो सब अनैतिक कार्य अपने आतंक के बलबूते पर कर देते हैं जिसके बाद उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ जाता है।

बालमुकुंद भी बन चुका था आतंक का पर्याय

अपने अवैध शराब कारोबार के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कांग्रेस से संरक्षण प्राप्त बालमुकुंद गौतम ने सामूहिक

विवाह जैसे आयोजनों को कर इंदौर संभाग स्तर पर अपना दबदबा बनाकर प्रदेश स्तरीय प्रभाव राजनीतिक व समाजसेवी स्तर पर स्थापित करने का प्रयास अपनी कूटनीति के साथ किया था।

अपने इसी प्रभाव के साथ झाबुआ, धार, इंदौर आदि के साथ गुजरात व राजस्थान तक अपने अवैध शराब के साम्राज्य को बढ़ाया और वे आतंक के मद में इतने मदहोश हो गए कि, बालमुकुंद के नियंत्रण में कार्य करने वाले उसके रिश्तेदार ने अपने ही पार्टी के एक नेता को एक महिला का सहारा लेकर मौत के घाट उतार दिया, पर कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं चाहे कितने भी चतुराई के साथ षड़यंत्र रच हत्या कर घटना को अंजाम दिया, लेकिन बालमुकुंद के नियंत्रण में काम करने वाले भाई के साथ सभी हत्यारे जेल की सलाखों में पहुंचे और आमजन के सामने कथित समाजसेवी बालमुकुंद की कारस्तानीयां कितने निचले स्तर तक अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए गडी गई जो सर्वसाधारण को विदित हो गया।

गूंज ने किया था पूर्व में गौतम का यह खुलासा

इतना ही नहीं गूंज ने बालमुकुंद की वह कारस्तानी भी उजागर की थी कि, अपने पैसे के बल पर बड़ा रोब रखने वाला कथित समाजसेवी के पास शराब के अवैध कारोबार के साथ बैंकों के मैंनेजरो से ऐसी सांठ-गांठ की कि, उसकी पत्नी परिवार के नाम के साथ जिस किसी शक्स से झाबुआ जिला हो या अन्य जगह वहां के स्थानीय जिन-जिन व्यक्तियों से पार्टनरशिप का व्यवसाय किया उसी के फर्म के नाम से पार्टनरशिप डिड व अलग-अलग फर्मों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर या फिर उसी शराब दुकान की पार्टनरशिप डिड के नाम पर बैंकों के कागजात पर हस्ताक्षर करवा-करवाकर करोड़ों रुपए ओडी लोन अपनी पत्नी व परिवार के नाम से दर्ज प्रॉपर्टी को गिरवी रख बैंकों से करोड़ों रुपए की राशि निकाल ली गई, लेकिन उक्त बात की भनक स्थानीय स्तर शराब के धंधे में पार्टनर रहे पार्टनरजनों को एक-एक कर तब लगी जब बैंकों में बालमुकुंद द्वारा न ही मूल रुपयों को भरा न ही ब्याज का रूपया भरा गया। तत्पश्चात संबंधित व्यक्तियों को रिकवरी हेतु बैंकों से नोटिस जारी हुए तो वे सभी पार्टनर ऐसे हक्का-बक्का हो गए थे कि, वे यह बात किसी को बता भी नहीं सकते और जब सभी एक-एक कर मिले तो कईयों के साथ कंप्रोमाइज कर अपनी प्रॉपर्टी की लेन-देन की तो, कईयों के आज भी बैंकों में सिर्फ ब्याज का रुपैया भरकर दूसरों के फर्मों के नाम से रुपया बैंको में बकाया है।

सकर्स मास्टर पप्पु भी चला शराब माफिया गौतम के नक्से कदम पर

कुछ इसी तरह झाबुआ कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस राज में खाद्यान्न की कालाबाजारी का रिंग मास्टर बन भाजपा की सरकार में खाद्यान्न की कालाबाजारी का सर्कस मास्टर बना। पप्पू की भी कारस्तानी इसी तरह की है, हमने पिछले अंक में स्पष्ट किया था कि, किस तरह से एक-एक लाख रुपए ब्याज से लेने वाला पप्पू आज खाद्यान्न की कालाबाजारी का सर्कस मास्टर बन गया है और पप्पू ने भी अपने खाद्यान्न रुपी कालाबाजारी का साम्राज्य बढ़ाने के लिए कूटनीति के साथ जिले के औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर के पास फुट तालाब में स्थित प्राचीन वनेश्वर हनुमान मंदिर पर बड़े-बड़े धार्मिक आयोजन कर वह आज धार्मिक व आस्था का केंद्र बनकर उमरा है। पिछले कुछ वर्षों में यहां बड़े धार्मिक आयोजनों ने इस मंदिर को प्रदेश व देश के धार्मिक स्थलों में पहचान दिलाई है और इसी धार्मिक आयोजनों के साथ खाद्यान्न की कालाबाजारी का सर्कस मास्टर पप्पू टीवी और समाचार-पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन जारी कर कथित समाजसेवी बन अपने प्रभाव को ऐसा स्थापित किया कि, जिले के साथ प्रदेश व गुजरात, राजस्थान में भी अपने खाद्यान्न की कालाबाजारी कर गरीबों का अनाज बेच-बेचकर करोड़ों में खेला जो आज जेल की सलाखों में है।

खैर पप्पू की कालाबाजारी की बड़ी पैहरिज के खेल में भाजपा क्या-क्या कालाबाजारी का खुलासा कार्यवाही के साथ कर पाती है या जिलेवासियों की माने तो आने वाले उपचुनाव में बड़ा डोनेशन चुनाव के नाम पर लेकर धार्मिक आस्था के नाम पर अपना प्रभाव बताने वाले सर्कस मास्टर पप्पू के खुलासे अधर में ही रह जाएंगे यह आगे देखने को मिलेगा।

श्री विश्व मंगल हनुमान तारखेड़ी तक निकाली पैदल यात्रा

माही की गूंज, झाबुआ।

शहर से सटे ग्राम गडवाड़ा स्थित हनुमान मंदिर से सोमवार देर शाम 7 बजे श्री विश्व मंगल हनुमान सेवा समिति से जुड़े सदस्यों द्वारा पद यात्रा निकाली गई। यात्रा में करीब 20 यात्री शामिल हुए। पैदल यात्रियों ने ग्राम गडवाड़ा से देवझिरी में शिवलिंग के दर्शन करते हुए अलसुबह करीब 6 बजे पेटलावद के समीप तारखेड़ी पहुंचकर विश्व मंगल हनुमानजी के दर्शन-वंदन का लाभ लिया। जिसके बाद ध्वजा अर्पण की।

विश्व मंगल हनुमान तारखेड़ी के शिखर पर ध्वजा चढ़ाने के लिए समिति के सदस्यों ने ग्राम गडवाड़ा में मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री रामजी तथा संकट मोचन हनुमान के दर्शन करते हुए जय श्री राम, जय हनुमान के जयघोष के साथ यात्रा आरंभ की। यात्रा का नेतृत्व समिति के प्रमुख अजय रामावत ने किया। सभी यात्री उत्साहपूर्वक संपूर्ण रास्ते में जगह-जगह जयघोष लगाते हुए अपने हाथों में ध्वज लेकर अगले मंगलर को अलसुबह 6 बजे तारखेड़ी धाम पहुंचे।

विश्व शांति तथा कोरोना मुक्ति के लिए की प्रार्थना

यहां पहुंचकर सभी श्रद्धालुओं ने अलसुबह जल्दी स्नान कर पहले विश्व मंगल के दर्शन किए। बाद भगवान के चरणों में ध्वज अर्पण कर संकट मोचन हनुमानजी से पूरे विश्व में सुख-शांति और कोरोना महामारी से मुक्ति दिलवाने हेतु प्रार्थना की।

बामनिया दुकान निर्माण मामले में ग्राम पंचायत और उपयंत्री आमने-सामने

माही की गूंज, झाबुआ।

बामनिया में मुख्य चौराहे पर सर्वे नंबर 144 का विवादित दुकान निर्माण मामला एक बार फिर सुर्खियो में है, जिसमें जनपद पंचायत पेटलावद में पदस्थ उपयंत्री नीरज पांचाल जो ग्राम पंचायत बामनिया में पदस्थ हैं, कलेक्टर झाबुआ, पुलिस अधीक्षक झाबुआ और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ को ग्राम पंचायत बामनिया एवं भाजपा नेता के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में उपयंत्री ने बताया कि, शनिवार 19 सितम्बर 2020 को सुबह सवा 7 बजे सरपंच पति मेरे घर पर आए और मुझ प्रार्थी को बामनिया सर्वे नंबर 144 मुख्य चौराहे पर बन रही दुकान का मूल्यांकन जो पहले से ही किसी प्राइवेट इंजीनियर द्वारा चढ़ा रखा था। उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। मेरे द्वारा जब मापदंड पुस्तिका एमबी देखी तो वह जनपद पंचायत पेटलावद एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पेटलावद के कार्य योजना की नहीं होते हुए बाजार से खरीदी गई मापदंड पुस्तिका थी, मेरे द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया और कहा गया कि, मुझे जनपद पंचायत पेटलावद से इस कार्य योजना के बारे में कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, जिसके बाद सरपंच पति ने संदीप मांडोत को उसके खुद के मोबाइल से फोन लगाया गया और मोबाइल का स्पीकर ऑन करके बात कराई गई। मांडोत ने मेरे परिवार के सामने ही मुझ प्रार्थी को गाली-गलौज कर धमकी दी गई व अश्लिल भाषा का उपयोग किया गया, जिसके बाद सरपंच पति ने भी जाते-जाते मुझे धमकी दी। नीरज पांचाल ने शिकायत में मांग की है कि, मेरी जान-माल एवं सुरक्षा को देखते हुए शासकीय कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में और गलत तरीके से फर्जी मूल्यांकन पर जबरदस्ती हस्ताक्षर का दबाव डालने के लिए सरपंच पति एवं संदीप मांडोत पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाए।

सरपंच ने लगाया दो लाख की रिश्वत का आरोप

उपयंत्री के आरोपो के बीच बामनिया ग्राम पंचायत सरपंच रामकन्या मखोड़ ने उपयंत्री पर ग्राम पंचायत के कार्यो के मूल्यांकन के लिए दो लाख रुपए मांगने ओर समय पर कार्य नही करने के गम्भीर आरोप लगाए है। उक्त पूरा मामला सीधे कलेक्टर के पास है और अब उन पर ही निर्भर करता हैं कि, वो मामले को किस तरह से हेंडल करते हैं। वही उपयंत्री नीरज पांचाल नें अपनी और से मोर्चा खोल दिया है और कार्यवाही नही होने पर मामले को इंजीनियर संघ भोपाल तक ले जाने का मन बना लिया है। चुंकी मामले में भाजपा ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी पर गम्भीर आरोप लगे हैं जिसके बाद मामले में जम कर राजनीति भी होना तय है और उपयंत्री के विरुद्ध कई मामलों में जाँच के नाम पर मामले को निपटाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया जाना भी तय है।

बाबू अटकान को मिला बाबू जोशी का साथ, अधिकारी अपनी कारिस्तानी छुपाने के लिए करते गए एक बाद एक फर्जीवाड़ा

फर्जी नियुक्ति के बाद, फर्जी वेतन भुगतान का मामला आया सामने

माही की गूंज, झाबुआ।

आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत पेटलावद में हुई फर्जी भर्तिया ओर खण्ड शिक्षा कार्यालय पेटलावद में पदस्थ बाबू रामचंद्र अटकान के परिवार और रिश्तेदारों की भर्ती का खुलासा गूंज द्वारा सिलसिलेवार किया गया। गूंज में मय दस्तावेजो के पूरे प्रमाण के साथ विभाग में भर्ती के नाम पर हुई हेरा-फेरी का मामला उजागर हुआ है। बाबू के और भी रिस्तेदार हैं जो बाबू के आशीर्वाद से आज भी फर्जी नियुक्ति लेकर नोकरी कर रहे हैं, जिनकी जानकारी भी सूचना अधिकार के माध्यम से जुटाई जा रही है। अभी तक पूरे मामले में खुलासे के बाद साफहै कि, केवल बाबू अटकान अकेला ही इस फर्जीवाड़े का जिम्मेदार नही बल्कि प्राचार्य प्रसाद, तत्कालीन बीईओ पेटलावद, सहायक आयुक्त झाबुआ, संभागीय उपायुक्त सहित कई लोग पूरी हेरा-फेरी में शामिल हैं, उक्त खुलासा होने के बाद भी विभाग के जिम्मेदार और कलेक्टर कुंभकर्णी निंद में सोए हुए है नतिजन अब तक उच्च अधिकारियों ने मामले में कोई संज्ञान नही लिया है न अब तक फर्जी नियुक्तियो में हुई हेरा-फेरी की जांच के कोई आदेश जारी हुए। यदि मामले की ईमानदारी से जाँच की जाती हैं तो न केवल पेटलावद बल्कि पूरे जिले में आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत पिछले कई वर्षो से चल रहे फर्जी भर्ती घोटाले के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश होगा और कई जिम्मेदार और कर्मचारियों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, तो कई कर्मचारियों को नोकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा ये भी तय है, बस आवश्यक्ता हे उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच की।

फर्जी नियुक्ति के बाद वित्तीय अनियमिता का मामला हुआ उजागर

बाबु रामचद्रं अटकान को मिला बाबु उपेंद्र जोशी का साथ

आदिवासी विकास विभाग में केवल भर्ती घोटाला ही नही बल्कि वित्तीय अनियमित्ताओं का मामला भी उजागर हो रहा है, जहाँ न्यायलय के साथ शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर नियम के विरुद्ध जाकर वेतन भुगतान कर भारी अनियमित्ता की गई, जिसकी शिकायत के बाद सभी जिम्मेदार जाँच में पल्ला झाड़ते रहे लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड की गई अनियमित्ताओ को फर्जी नियुक्ति की तरह फर्जी भुगतान को भी अनदेखा कर भ्रष्टों को बचाया गया। शिकायतकर्ता रमेश धानक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम में प्राप्त दस्तावेजो से मामला उजागर हुआ, जिसका खुलासा मय दस्तावेजों के साथ परत दर परत किया जाएगा कि, कैसे कायदे-कानून को अपने बाप की बबुती मान कर उसे ताक में रखकर हटाई गई दैनिक वेतन भोगी की वेतन की राशि का भुगतान किया और कैसे उसकी चलती जांच में नियम के विरुद्ध नियुक्ति कर दी गई।

बाबू अटकान को मिला बाबू जोशी का साथ

बीईओ कार्यालय में पदस्थ बाबू रामचंद अटकान इस पूरे खेल की सबसे मजबूत सीडी हुआ करती थी जो कि, गूंज के खुलासे के बाद अब कमजोर सीडी साबित हो रही हैं, जिसके कारण पूरे आदिवासी विकास विभाग में चल रहे हेरा-फेरी के खेल का खुलासा जल्द ही होगा ये तय है। बरहाल अटकान की कारिस्तानीयो को उसके ही विभाग में पदस्थ एक ओर कलीग लेखपाल उपेंद्र कुमार जोशी का साथ मिला जिसने साथी बाबू से मिलीभगत कर बाबू के कार्य से हटाए गए दैनिक वेतन भोगी रिस्तेदार के वेतन का भुगतान नियम के विरुद्ध कर भारी वित्तीय अनियमित्ता की है जिसका खुलासा भी गूंज की बेबाकी के साथ चल रही सीरीज में मय प्रमाणित दस्तावेजो, बिल-वाउचर, आदेश और श्रम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के साथ किया जाएगा।

न्यायालय में होगी मुलाकात- रमेश धानक

परत दर परत गूंज में फर्जी नियुक्ति घोटाले का खुलासा मय प्रमाण के साथ शिकायतकर्ता रमेश धानक द्वारा उपलब्ध कराए गए पुख्ता एवं प्रमाणित दस्तावेजो के साथ करना शुरू किया तो पहली खबर के साथ ही बाबू हर प्रकार से गूंज की कलम को दबाने के प्रयास में लग गया, जब बाबू अटकान के सारे पैतरे फैल होते दिखे तो बाबू ने वकील के माध्यम से गूंज प्रतिनिधियो सहित शिकायतकर्ता को नोटिस भेजकर शिकायतकर्ता और गूंज की आवाज को दबाने का प्रयास शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता रमेश धानक ने फर्जी नियुक्ति में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बाबू रामचंद्र अटकान को दो टूक मे जवाब देकर कहा है कि, यदि रामचंद्र अटकान ने न्यायालय में जाने का निर्णय किया है तो वो उसका स्वागत करता है और सारे दस्तावेज प्रमाणित रूप से न्यायालय में पेश कर सच सबके सामने लाकर फर्जीवाड़े में शामिल सभी जिम्मेदारो ओर शासन को गुमराह ओर धोखाधड़ी करने वालो को जेल पहुचाएगा। शिकायतकर्ता व सुचना अधिकार का कार्यकर्ता रमेश धानक ने गूंज के द्वारा मामले में किए जा रहे खुलासे की भी सहराना करते हुए कहा है कि, न्याय की इस लड़ाई में यदि गूंज की तरह साथ समय पर मिला होता तो अब तक कई लोग जेल पहुँच चुके होते।

शिकायतकर्ता रमेश घानक

निरन्तर ...

अब नवरात्रि त्यौहार भी चढ़ा कोरोना की भेंट

6 फीट से ऊंची नहीं होंगी प्रतिमाएं, त्यौहारों के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी

माही की गूंज, झाबुआ

एक के बाद एक भारत सरकार गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 के आदेश एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश तथा धार्मिक कार्यक्रम व त्यौहार के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में आगामी माह में 17 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व आरंभ होने से विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाओं एवं झांकियों की स्थापना करने के संबंध में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रहते हुए जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोकशांति बनाएं रखने के लिए कलेक्टर सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत झाबुआ जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में आदेश पारित किया है। आदेश में बताया गया कि, विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 6 फिट होगी तथा पंडाल का साईज अधिकतम 10 बाय 10 फीट रखा जा सकेगा। सभी मूर्तिकारों के लिए प्रतिमा की ऊंचाई 6 फिट या उससे कम रखा जाना जरूरी है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह विभाग मप्र शासन के निर्देशानुसार 100 से कम व्यक्तियों की उपस्थिति के आयोजन किए जा सकेगें तथा इसके लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। इसके लिए संबंधित आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालुओं द्वारा मॉस्क, सोशल डिसटेंसिंग एवं सेनेटाईजर के प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422